RNI NO. DELHIN/2015/61881

www.srojvarta.in

मूल्य : 10 रूपये

सरोज वार्ता

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका | वर्ष-12 | अंक- 07 | पृष्ठ- 44 | जुलाई 2026



ऊर्जा क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक छलांग: स्वच्छ ऊर्जा से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की ओर तेज़ी



मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी सशक्तीकरण

शक्ति से समृद्धि



नारी
उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी

नवनिर्माण के 9 वर्ष

सुरक्षा से समझौता नहीं
सभी थानों में 'मिशन शक्ति' केंद्र

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
26.81 लाख+
बेटियां सशक्त

निराश्रित महिलाओं को पेंशन

लखपति दीदी योजना
18.55 लाख+
महिलाएं बनीं लखपति



महिला श्रम बल भागीदारी
13% से बढ़कर 36%

1 करोड़+
ग्रामीण महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

मेधावी छात्राओं को स्कूटी का उपहार

कामकाजी महिलाओं के लिए
श्रमजीवी महिला छात्रावास

महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड
ब्याज मुक्त ऋण

10,400+
स्टार्ट-अप का नेतृत्व

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

BREAKING NEWS

www.srojvarta.in



RNI NO. DELHIN/2015/61881
राष्ट्रीय
सरोज वार्ता
हिन्दी मासिक पत्रिका
मूल्यः 10 रूपये
वर्ष-12 । अंक - 07 । जुलाई 2026
संरक्षक : रामकुमार सिंह
प्रधान संपादक : जगत किशोर सोलंकी
संपादक : अनुराग प्रताप
विधि सलाहकार : ललित पराशर
ग्राफिक डिजाइनर : सहदेव माहौर
मार्किटिंग मेनेजर : कृष्ण कुमार (उत्तर प्रदेश)

ब्यूरो प्रमुख
उत्तर प्रदेश : कृष्ण कुमार
राजस्थान : सौमेंद्र सिंह
दिल्ली : रिचा जौशी
छत्तीसगढ़ : विजय कुमार

संपादकीय, विज्ञापन एवं प्रसार कार्यालय
सरोज वार्ता, आर जेड ए 3/73 गली न. 3ए दुर्गा पार्क
नई दिल्ली-110045

फोनं,: 09456004121, 09555253051,
9899864010

www.srojvarta.in
sarojvartanews@gmail.com
srojvartanews@gmail.com

क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तर प्रदेश)
नियर हनुमार मंदिर, अमापुर सिद्धपुर
रोड़, सिद्धपुर जिला, कासगंज

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। सभी पद अवैतनिक हैं। विज्ञापन की सत्यता की जांच स्वयं कर लें। इसकी जिम्मेदारी उनकी है, एवं इसके प्रकाशक एवं संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायलय के अधीन होगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अनुराग प्रताप
द्वारा मैसर्स जवाद लीठोफराफर
(M/s Jawaad Lithofrapher)
3622, दीनाबेग, लाल कुंआ, दिल्ली : 6
द्वारा मुद्रित व आर.जेड.
ए : 3/73, गली नं. 3ए दुर्गा पार्क नई
दिल्ली : 45 से प्रकाशित

संपादक : अनुराग प्रताप

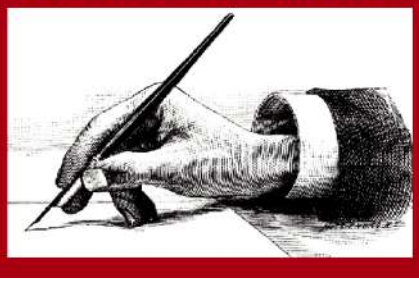
पैदल यात्रियों का हक

जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि सुरक्षित और तयशुदा फुटपाथ पर चलना आम व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, तो इसके खास मायने हैं। अदालत उस हकीकत की ओर नीति-नियंताओं का ध्यान दिलाती है, जिसे अब तक भारतीय शहरों के नियोजन में नजरअंदाज किया गया। निश्चित रूप से सड़कों पर पहला हक लोगों का है, बाद में गाड़ियों का। सही मायने में कोर्ट ने पैदल चलने वाले लोगों के अधिकारों को जीवन, आजादी और कहीं भी आने-जाने की गारंटी से जोड़कर सार्थक पहल की है। अदालत ने इस तरह नागरिक जीवन की एक बुनियादी जरूरत को सार्वजनिक जवाबदेही का मुद्दा बना दिया है। यह एक हकीकत है कि देश के करोड़ों भारतीयों के लिये पैदल चलना रोजमर्रा की जरूरत है, न कि जीवनशैली का विकल्प। इनमें तमाम स्कूल जाने वाले बच्चे, बाजार जाने वाले बुजुर्ग, कम दूरी तक आने-जाने वाले कामगार और दिव्यांग लोग शामिल हैं, जिनके लिये सुरक्षित पैदल यात्रा जीवन की एक सुविधा है। यह विडंबना ही है कि अक्सर रेहड़ी-खोमचे वाले, गलत तरीके से सड़कों में खड़ी गाड़ियां और निर्माण कार्य से जुड़ा मलबा पैदल यात्रियों के रास्ते पर अतिक्रमण कर देता है। यही वजह है कि पैदल यात्रियों को व्यस्त सड़कों पर चलने के लिये मजबूर होना पड़ता है। जिससे अकसर उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा है कि गाड़ी चलाने वाले पैदल चलने वाले लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही मायने में यह टिप्पणी वाहन केंद्रित शहरी नियोजन की सोच पर सीधे प्रहार करती है। यह विडंबना ही है कि शहरी सड़क परियोजनाओं में ट्रैफिक के प्रवाह को प्राथमिकता दी गई है। वहीं फुटपाथ को गैर जरूरी माना गया है। इसकी ही वजह से अकसर होने वाले सड़क हादसों का शिकार पैदल यात्रियों को होना पड़ता है। इसी दोषपूर्ण नीति के चलते ही लगातार पैदल चलने की जगह सिमटती रही है और सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि सड़क हादसों में इस साल 36,526 पैदल यात्रियों की मौत हुई है। मरने वालों का यह आंकड़ा सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या का 20.26 प्रतिशत है। यही वजह है कि कोर्ट को पैदल चलने वाले लोगों के अधिकार की सुरक्षा के लिये एक कानूनी ढांचा बनाने पर जोर देना पड़ा है। वास्तव में पैदल यात्रियों की रक्षा के लिये कानून तो पहले से ही हैं, मगर ये बिखरे हुए हैं। यदि एक व्यापक कानून बनता है तो फुटपाथ के डिजाइन, यात्रियों की पहुंच, फुटपाथों के रखरखाव और जवाबदेही के लिये मानकों का निर्धारण संभव हो सकेगा। इस संकट के समाधान के लिये नगर निकायों को अतिक्रमण-रोधी नियमों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए। वास्तव में तभी कोई शहर सचमुच आधुनिक बनता है, जब वह ज्यादा कारों को जगह देने के बजाय हर आम नागरिक को सुरक्षित और सम्मान के साथ चलने की सुविधा प्रदान करता है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है, अब सरकारों का काम उस पर चलना है।

● अनुराग प्रताप



जगत किशोर सोलंकी



सेहत पर भारी विकास

इस बात में दो राय नहीं कि हरियाणा की समृद्धि में औद्योगिक विकास की बड़ी भूमिका रही है। जिसमें बड़ी संख्या में राज्य के लोगों को रोजगार भी मिला है। हरियाणा अपनी औद्योगिक सफलता की प्रेरक कहानी पर गर्व करता रहा है। मानेसर के ऑटोमोबाइल हब से लेकर राज्य भर में फैले मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के उद्योगों में बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर पैदा हुए हैं। निस्संदेह, इससे राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिली है। लेकिन इस विकास की दूसरी तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह बात चिंतित करने वाली है कि राज्य में तीन हजार औद्योगिक इकाइयों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पर्याप्त उपकरण ही नहीं लगे हैं। जो एक गंभीर स्थिति को दर्शाती है। निस्संदेह, कोई भी विकास साफ हवा की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। चिंता की बात यह भी है कि प्रदूषण नियामक उपकरणों की कमी वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची में मानेसर सबसे ऊपर पाया गया है। यह औद्योगिक टाउनशिप न केवल हरियाणा का प्रमुख आर्थिक इंजन है, बल्कि हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों का घर भी है। जो आज हर दिन कारखानों से निकलने वाले धुएं से प्रभावित हवा में सांस लेने को अभिशप्त हैं। विडंबना यह है कि अब तक इस संकट को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई सार्थक पहल भी नहीं हुई है। बड़ी विचित्र बात है कि गाहे-बगाहे हर साल मौसमी स्मॉग या पराली जलाने को लेकर आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता रहता है। जबकि कोई वैज्ञानिक अध्ययन भी हमारे सामने नहीं आया कि स्मॉग व पराली जलाने की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण में कितनी भूमिका होती है। लेकिन जिन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण को हम नाप कर नियंत्रित कर सकते हैं, उस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की गई। सालभर चलने वाली औद्योगिक उत्सर्जन की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि वर्ष पर्यंत होने वाले औद्योगिक उत्सर्जन से हवा की गुणवत्ता खराब ही होती है। जिससे सांस संबंधी रोगों को बढ़ावा मिलता है। ये स्थितियां लोगों के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट ही पैदा करती हैं। विडंबना यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील इलाकों, विशेष रूप से देश के नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही का अच्छे से पता होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इसके बावजूद हजारों इकाइयां नियमों को ताक पर रखकर मुनाफा कमाने में लगी हैं, वह भी हजारों लोगों की सांसों की कीमत पर। यह नियामक तंत्र द्वारा नियमों को लागू करने और जवाबदेही तय करने में बड़ी नाकामी को ही दर्शाता है। इस जटिल समस्या का समाधान सिर्फ नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। वह बात अलग है कि कुछ छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों को साफ-सुथरी टेक्नोलॉजी अपनाने के लिये तकनीकी सहायता और आर्थिक मदद की जरूरत हो सकती है। इसके बावजूद प्रदूषणरोधी उपकरण लगाने की समय-सीमा और निर्धारित मानकों को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सही मायने में चेतावनी के बावजूद बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह एक हकीकत है कि साफ हवा औद्योगिक विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। यही स्थायी व दूरगामी परिणामों वाले विकास की अपरिहार्य शर्त भी है। सही मायनों में हरियाणा की अर्थव्यवस्था तब तक फल-फूल नहीं सकती, जब तक यहां के लोगों को अपनी सेहत की कीमत पर यह विकास करना पड़े। इसमें दो राय नहीं कि प्रगति और विकास की दृष्टि से राज्य के उद्योगों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इन उद्यमियों ने इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की कसौटी पर अपनी बेहतर क्षमताओं को साबित किया भी है। अब उन्हें इस बात के लिये प्रेरित करना होगा कि वे अब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने में भी वैसी ही प्रतिबद्धता दर्शाएं। सही मायने में किसी भी समाज में असली समृद्धि तभी आ सकती है जब हमारी प्राथमिकताओं में जन-स्वास्थ्य पहले हो।



ऊर्जा क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक छलांग: स्वच्छ ऊर्जा से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की ओर तेज़ी

सरोज वार्ता/ब्यूरो

भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर अग्रसर है। बढ़ती बिजली की मांग, स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण देश वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। हाल के वर्षों में सौर, पवन, जलविद्युत, बायो-ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। भारत आज नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुँच चुका है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता हासिल करना है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार देश में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता लगातार बढ़ रही है और ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज की गई हैं। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार आने वाले वर्षों में देश की अधिकतम बिजली मांग लगभग 300 गीगावाट तक पहुँच सकती है। इस बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ग्रिड आधुनिकीकरण, बैटरी ऊर्जा भंडारण, घरेलू सौर उपकरण निर्माण तथा ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। हाल ही में देश के बिजली मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक दर्ज होना भारत के ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी की दिशा में बड़ा कदम है। ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे निवेश का प्रभाव केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। इससे रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र, हरित हाइड्रोजन, स्मार्ट ग्रिड और ग्रामीण विद्युतीकरण को भी नई गति मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन अवसंरचना और घरेलू विनिर्माण पर इसी प्रकार ध्यान केंद्रित रहा, तो भारत आने वाले वर्षों में विश्व की अग्रणी स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

● ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे निवेश का प्रभाव केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। इससे रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र, हरित हाइड्रोजन, स्मार्ट ग्रिड और ग्रामीण विद्युतीकरण को भी नई गति मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन अवसंरचना और घरेलू विनिर्माण पर इसी प्रकार ध्यान केंद्रित रहा, तो भारत आने वाले वर्षों में विश्व की अग्रणी स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा का तेज़ विस्तार

देशभर में बड़े सौर पार्क, पवन ऊर्जा परियोजनाएँ और रूफटॉप सोलर कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और निवेश दोनों में वृद्धि हो रही है।

ऊर्जा सुरक्षा होगी मजबूत

घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

रोजगार और उद्योग को मिलेगा बल

ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश से विनिर्माण, इंजीनियरिंग, निर्माण, अनुसंधान तथा सेवा क्षेत्रों में व्यापक रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।

हरित हाइड्रोजन बनेगा भविष्य का ईंधन

भारत स्वच्छ ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन के विकास पर विशेष बल दे रहा है, जिससे उद्योग और परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने

में मदद मिल सकती है।

ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाएँ

- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
- सौर ऊर्जा से बदलता ग्रामीण भारत
- ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण
- भविष्य की बिजली व्यवस्थाः स्मार्ट ग्रिड और बैटरी स्टोरेज

भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैंः

भारत की प्रमुख ऊर्जा उपलब्धियाँ

- नवीकरणीय ऊर्जा का तेज़ विस्तार
- भारत विश्व के अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल है।
- सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है।
- 500 गीगावाट का लक्ष्य (2030)
- भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सौर ऊर्जा में बड़ी प्रगति

राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में विशाल सौर पार्क स्थापित किए गए हैं। रूफटॉप सोलर और पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं से घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है।

पवन ऊर्जा में मजबूत स्थान

तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक पवन ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

भारत ने स्वच्छ ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है।

बिजली पहुँच का विस्तार

देश के लगभग सभी गाँवों तक बिजली पहुँचाई जा चुकी है और घरों तक बिजली कनेक्शन का दायरा काफी बढ़ा है।

राष्ट्रीय बिजली ग्रिड का सुदृढ़ीकरण

'वन नेशन, वन ग्रिड' की दिशा में ट्रांसमिशन नेटवर्क का व्यापक विस्तार हुआ है, जिससे राज्यों के बीच बिजली का आदान-प्रदान अधिक प्रभावी हुआ है।

ऊर्जा दक्षता

एलईडी बल्ब, ऊर्जा-कुशल उपकरणों और ऊर्जा बचत कार्यक्रमों ने बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन कम करने में योगदान दिया है।

परमाणु एवं जलविद्युत

परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं और जलविद्युत उत्पादन क्षमता में भी निरंतर विस्तार हो रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना

देशभर में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ रही है, जिससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत का ऊर्जा क्षेत्रः प्रमुख संस्थान और उनकी भूमिका

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत

ऊर्जा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और सामाजिक समृद्धि की आधारशिला होती है। बिजली, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्रोत आधुनिक जीवन, उद्योगों और आधारभूत संरचना को गति प्रदान करते हैं। भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र के बीच व्यापक समन्वय स्थापित किया गया है। आज भारत का लक्ष्य केवल ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इस दिशा में विभिन्न मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ और वित्तीय संस्थान मिलकर देश के ऊर्जा परिवर्तन को नई गति दे रहे हैं।

विद्युत मंत्रालयः बिजली क्षेत्र की नीति और विकास का केंद्र

भारत में विद्युत क्षेत्र की नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन का दायित्व विद्युत मंत्रालय के पास है। यह मंत्रालय बिजली उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण से जुड़ी राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करता है तथा राज्यों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। देशभर में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत बनाना, विद्युत वितरण सुधार, स्मार्ट मीटरिंग और बिजली क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देना मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE): हरित ऊर्जा का नेतृत्व

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति का





प्रमुख आधार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। यह मंत्रालय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-ऊर्जा, लघु जलविद्युत, अपशिष्ट से ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है। देश में विशाल सौर पार्कों की स्थापना, रूफटॉप सोलर कार्यक्रम, ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ तथा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे कार्यक्रम इसी मंत्रालय के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति बनाने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

•पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय: ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा

भारत की ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। यह मंत्रालय कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन, आयात, भंडारण, रिफाइनिंग और विपणन से संबंधित नीतियाँ तैयार करता है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना इसकी प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं।

•कोयला मंत्रालय: पारंपरिक ऊर्जा का मजबूत आधार

यद्यपि भारत तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, फिर भी देश के बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले पर आधारित है। कोयला मंत्रालय देश में कोयले के उत्पादन, खनन और आपूर्ति की व्यवस्था का संचालन करता है। ताप विद्युत संयंत्रों और इस्पात, सीमेंट जैसे उद्योगों को निरंतर ईंधन उपलब्ध कराकर यह मंत्रालय देश की ऊर्जा व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

•परमाणु ऊर्जा विभाग: दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत

परमाणु ऊर्जा विभाग देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों, अनुसंधान और तकनीकी विकास का संचालन करता है। परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ, विश्वसनीय और दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोत माना जाता है, जो भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

•सार्वजनिक क्षेत्र के ऊर्जा उपक्रम: विकास की आधारशिला

भारत के ऊर्जा क्षेत्र की मजबूती में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

•एनटीपीसी लिमिटेड देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है, जो तापीय, जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन कर रही है। कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण जैसे उभरते क्षेत्रों में भी निवेश कर रही है।

•पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राष्ट्रीय बिजली पारेषण प्रणाली की रीढ़ है। यह उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों को जोड़कर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

•एनएचपीसी लिमिटेड जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और संचालन में अग्रणी सार्वजनिक उपक्रम है तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।

•कोल इंडिया लिमिटेड देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, जो बिजली संयंत्रों और उद्योगों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

•ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाती है और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

•इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम देशभर में रिफाइनिंग, विपणन और ईंधन वितरण के माध्यम से करोड़ों उपभोक्ताओं तक पेट्रोलियम उत्पाद पहुँचाती हैं। ये कंपनियाँ जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भी निवेश बढ़ा रही हैं।

•गेल (इंडिया) लिमिटेड देश के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क, गैस परिवहन और विपणन में अग्रणी कंपनी है तथा गैस आधारित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

•वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका

ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए विशाल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इस दिशा में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी लिमिटेड जैसी संस्थाएँ बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

इनके अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान तथा अंतरराष्ट्रीय निवेश एजेंसियाँ भी ऊर्जा अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण निवेश कर रही हैं।

•ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भारत



आज भारत केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में हो रहे निवेश भविष्य की नई संभावनाओं को जन्म दे रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, नियामक निकायों और अनुसंधान संस्थानों का संयुक्त प्रयास भारत को ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। आने वाले वर्षों में यही संस्थान देश की विकास यात्रा को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे।



प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र बनेगा 'विकसित हरियाणा-2047' का आधार: मुख्यमंत्री



सरोज वार्ता/ब्यूरो

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत-2047' के संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार ने 'विकसित हरियाणा-2047' के व्यापक विजन पर कार्य शुरू कर दिया है। इसी उद्देश्य से आज प्रदेश के सभी विधायकों के साथ आयोजित बैठक में 'विकसित हरियाणा-2047' के बारे में चिंतन किया गया। इस अभियान की थीम 'मेरी विकसित विधानसभा' रखी गई है, जिसके माध्यम से विकसित हरियाणा की शुरुआत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से होगी।उन्होंने कहा कि हरियाणा को समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के लिए अगले 20 वर्षों का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का 'विजन चैंपियन' बनकर क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की प्राथमिकताओं की पहचान करेगा तथा विकास की कार्ययोजना तैयार करेगा। इस अवसर पर पर्यटन एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा भी उपस्थित थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचाना, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 40 लाख रुपये से अधिक करना, महिला श्रम भागीदारी को 45 प्रतिशत से ऊपर ले जाना तथा महिला साक्षरता को 100 प्रतिशत तक पहुंचाना शामिल है। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा हर घर तक पाइप के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 'मेरी विकसित विधानसभा अभियान' के अंतर्गत जुलाई और अगस्त माह में सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान गांवों, वार्डों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों तथा सामाजिक संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। इन सुझावों के आधार पर विकसित हरियाणा का जनभागीदारी आधारित रोडमैप तैयार किया जाएगा।उन्होंने कहा कि इस अभियान में शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा जल, स्वच्छता एवं पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक बेटी को शिक्षित, प्रत्येक युवा को कुशल और प्रत्येक हाथ को रोजगार उपलब्ध कराना है। रोजगार क्षमता को 95 प्रतिशत तक पहुंचाने तथा आईटीआई, पॉलीटेक्निक और कॉलेजों को उद्योगों से जोड़ने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर को 10 से कम तथा शिशु मृत्यु दर को 5 से कम करने, 100 प्रतिशत टीकाकरण और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जल एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने तथा नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 70 प्रतिशत से अधिक करने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल एक सरकार या एक कार्यकाल तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष 2047 तक हरियाणा के भविष्य की दीर्घकालिक कार्ययोजना है। इससे पहले की सरकारों में केवल चुनावों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती थी, वे पार्टियां केवल 5 साल की सोच के साथ अपना घोषणापत्र जारी करती थी और उनमें से कुछ ही घोषणाओं पर काम होता था। शेष घोषणाओं को डेंटिंग-पेंटिंग करके अगले साल के लिए पुनः प्रस्तुत कर दिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार 20-20 साल की योजनाएं बना रही हैं और इनके क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम भी उठा रही है। विकसित हरियाणा-2047 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक विभाग के वार्षिक लक्ष्य तय किए जाएंगे, उनकी नियमित समीक्षा की जाएगी तथा डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की प्रगति की व्यक्तिगत समीक्षा वे स्वयं करेंगे।श्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित हरियाणा, विकसित भारत की प्राणशक्ति बनेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा।इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू, ओएसडी श्री वीरेंद्र सिंह बड़खालसा, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक कैप्टन मनीष कुमार लोहान तथा मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीन अत्रे भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च साधन बनाया

सरोज वार्ता/ब्यूरो

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ क्षण ऐसे हैं जो केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं होते, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं और विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के देश की जनता के निरंतर विश्वास के साथ ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त कर दीर्घकाल तक राष्ट्र का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त करना गौरवपूर्ण क्षण है। यह केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण के संकल्प, सेवा और सुशासन की विजय है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा का सर्वोच्च साधन बनाया। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। आज विश्व भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति, विश्वसनीय साझेदार और भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हुई है और यह परिवर्तन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच तथा निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होना केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, यह भारत की जनता के अटूट विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। निरंतर जनसमर्थन किसी पद या प्रचार से नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण, पारदर्शिता, निर्णायक नेतृत्व और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की कार्य शैली से अर्जित होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं को सदैव 'प्रधान सेवक' के रूप में प्रस्तुत किया और गरीब, किसान, महिला, युवा तथा समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सतत प्रयास किया। यही कारण है कि देश की जनता ने बार-बार उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया। उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, अथक कार्यशक्ति, दूरदर्शी सोच और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्पष्ट संकल्प करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है तथा उन्हें जन-जन का प्रिय नेता बनाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, आधारभूत संरचना, रक्षा क्षमता, अंतरिक्ष विज्ञान और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि और डिजिटल इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रमों से करोड़ों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। शासन की योजनाएँ पहली बार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पारदर्शी ढंग से पहुँची हैं। भारतीय



संस्कृति और आस्था के पुनर्जागरण का भी यह कालखंड इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों भारतीयों की सदियों पुरानी आस्था की पूर्ति का क्षण था। यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और आत्म गौरव का पुनर्स्थापन था। जम्मू-कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों ने राष्ट्रीय एकीकरण को नई मजबूती प्रदान की। विकास और लोकतंत्र की मुख्यधारा से जुड़ते हुए जम्मू-कश्मीर आज नए अवसरों की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी ने यह सिद्ध किया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति के साथ कठिन से कठिन निर्णय भी राष्ट्रहित में लिए जा सकते हैं। मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री श्री मोदी के विशेष स्नेह और मार्गदर्शन का लाभ निरंतर प्राप्त करता रहा है। प्रदेश में सड़क, रेल, सिंचाई, ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश एवं परियोजनाओं ने विकास को नई गति दी है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में बदलाव लाने वाली अनेक योजनाओं का प्रभाव प्रदेश के प्रत्येक जिले तक पहुँचा है। विंध्य क्षेत्र और विशेष रूप से मेरा गृह क्षेत्र रीवा भी इस परिवर्तनकारी यात्रा का साक्षी बना है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट ने न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। यह परियोजना प्रधानमंत्री जी के उस विजन का प्रतीक है जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलते हैं। आज रीवा देश के ऊर्जा मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विंध्य की पहचान नई संभावनाओं से जुड़ चुकी है। विंध्य क्षेत्र में सड़क संपर्क, रेल सुविधाओं, शिक्षा संस्थानों और आधारभूत संरचना के विस्तार ने विकास के नए द्वार खोले हैं। यह क्षेत्र अब पिछड़ेपन की पहचान से आगे बढ़कर प्रगति और संभावनाओं के केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और केंद्र सरकार का सतत सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे यह अनुभव करने का अवसर मिला है कि प्रधानमंत्री जी की सोच केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ भारत के व्यापक निर्माण की है। आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजना ने गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं ने मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी है। प्रदेश सरकार भी प्रधानमंत्री जी के इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नेतृत्व हमें यह विश्वास देता है कि विकसित भारत का संकल्प केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक साकार होती राष्ट्रीय यात्रा है। उनके नेतृत्व में भारत ने आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज प्रत्येक भारतीय गर्व के साथ कह सकता है कि उसका देश विश्व पटल पर नई ऊँचाइयों को छू रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे युग निर्माता नेतृत्व के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

भारतीय चिंतन में आदर्श नेतृत्व का आधार सदैव लोक कल्याण और राष्ट्रहित रहा है।

'प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम॥'

शासक का सुख प्रजा के सुख में और उसका हित प्रजा के हित में निहित होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जनसेवा, सुशासन और राष्ट्र प्रथम की यही भावना निरंतर परिलक्षित होती है। मध्यप्रदेश और विंध्य की जनता की ओर से मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र सेवा की अक्षुण्ण ऊर्जा प्रदान करें, ताकि उनके नेतृत्व में भारत विकसित, आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल संबंधी मुद्दों का हो रहा सकारात्मक समाधान

राजस्थान को जल्द मिलेगा अपने हिस्से का पानी, जल प्रबंधन को मिलेगी और मजबूती: मुख्यमंत्री



सरोज वार्ता/संवाददाता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ यमुना जल परियोजना से संबंधित बैठक में भाग लिया। बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही, किशाऊ बांध परियोजना से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 'जल है तो कल है' की भावना के साथ राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यमुना जल परियोजना को प्रभावी एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत पानी को पारंपरिक नहर प्रणाली की बजाय पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है, जिससे जल संरक्षण सुनिश्चित होने के साथ ही वितरण व्यवस्था अधिक व्यापक बनेगी।

किशाऊ बांध परियोजना से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा को मिलेगा पानी: उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े छह राज्यों के मुद्दों का भी समाधान हो गया है और शीघ्र ही उससे संबंधित एमओए भी किया जाएगा। इससे राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा सहित अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से भविष्य में जल संबंधी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल परियोजना राजस्थान विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र एवं हरियाणा सरकार के सहयोग से परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दशकों से लंबित परियोजनाओं को गति मिल रही है तथा राज्यों के बीच जल संबंधी मुद्दों का सकारात्मक समाधान निकल रहा है। राजस्थान को भी यमुना जल उपलब्ध कराने की मांग लंबे समय से की जा रही थी और अब इस दिशा में ठोस प्रगति हो रही है।

किसानों, उद्योगों और आमजन को मिलेगा व्यापक लाभ: मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन से जल्द ही राजस्थान को अपने हिस्से का पानी प्राप्त होगा, जिससे किसानों, उद्योगों और आमजन को व्यापक लाभ मिलेगा। साथ ही, प्रदेश में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने में भी सहायता मिलेगी।

हर व्यक्ति तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करना लक्ष्य - नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर व्यक्ति तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकारें प्रतिबद्धता से काम कर रही हैं। इसी के तहत रेणुका, लखवार और किशाऊ परियोजनाओं के क्रियान्वयन से मिलने वाले पानी से राजस्थान, दिल्ली के साथ हरियाणा के लोगों को भी फायदा मिलेगा। बैठक में वर्षा के पानी को भी सहेजकर राजस्थान पहुंचाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में केन्द्र सरकार, राजस्थान के जल संसाधन विभाग तथा हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

यूपी में बढ़े पर्यटक तो योगी सरकार ने किया 'होम स्टे नीति' में बड़ा बदलाव

पर्यटन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप किया गया संशोधनः मंत्री जयवीर सिंह



सरोज वार्ता/संवाददाता

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही पर्यटन गतिविधियों और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होम स्टे नीति-2025 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नई व्यवस्था के तहत होम स्टे और बीएंडबी इकाइयों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पहले से और आसान बनाया गया है। साथ ही पंजीकृत इकाइयों को ऑनलाइन स्वतः नवीनीकरण (ऑटो रिन्यूअल) की सुविधा भी प्रदान की गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि योगी सरकार का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और स्थानीय लोगों को भी पर्यटन से जुड़ने के अधिक अवसर मिल सकें।

6 की जगह अब 8 कमरों के लिए मिली मंजूरी: उन्होंने बताया कि संशोधित नीति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में संचालित होम स्टे इकाइयों में अब न्यूनतम एक और अधिकतम आठ कमरे (16 बेड) पंजीकृत कराए जा सकेंगे। पूर्व में अधिकतम 6 कमरों को ही किराये पर दिए जाने की व्यवस्था थी। यह भी साफ किया गया है कि शहरी इलाकों में होम स्टे ऐसी रिहायशी प्रॉपर्टी में चलने चाहिए जो या तो आवेदक की अपनी हो या फिर विकास प्राधिकरण से लीज पर ली गई जमीन पर बनी हो। प्रॉपर्टी के मालिक या उनके परिवार के सदस्यों का वहीं रहना जरूरी है।

पर्यटकों को आवास के साथ भोजन की सुविधा: बीएंडबी श्रेणी के अंतर्गत आवासीय अथवा लीज पर लिए गए भवनों में अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत किए जा सकेंगे। ऐसी इकाइयों में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को आवास के साथ नाश्ता और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इकाई में केयरटेकर का निवास अनिवार्य होगा और लीज पर लिए गए भवन की लीज अवधि न्यूनतम तीन वर्ष होनी चाहिए। 16 बेड वाली डॉरमेट्री भी इस श्रेणी में पात्र मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि आठ कमरों से अधिक क्षमता वाले आवासीय भवनों, होटल, मोटल और गेस्ट हाउस जैसी इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

तीन महीने पहले होगा स्वतः नवीनीकरण: संशोधन के तहत पंजीकृत इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए पोर्टल आधारित स्वतः नवीनीकरण (ऑटो रिन्यूअल) की व्यवस्था भी लागू की गई है। अब इकाई संचालक अपने पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से पूर्व विभागीय पोर्टल पर स्वयं नवीनीकरण करा सकेंगे। यह सुविधा पंजीकरण समाप्ति की तिथि से तीन माह पूर्व उपलब्ध रहेगी।

पर्यटन आधारित रोजगार बढ़ेंगे: अपर मुख्य सचिव पर्यटन विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि यह संशोधन प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देने और पर्यटन आधारित रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भागीदारी आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण आवास क्षमता बढ़ाने के लिए यह कदम विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा।

महतारी वंदन योजना : महिला सशक्तिकरण की नई इबारत, आत्मनिर्भरता और सम्मान का सशक्त आधार



सरोज वार्ता/ब्यूरो

किसी भी समाज और राज्य के विकास की वास्तविक तस्वीर तब उभरती है, जब उसकी महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त हों। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना इसी सोच को साकार कर रही है। यह योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में आर्थिक संबल, आत्मविश्वास और सम्मान का नया अध्याय जोड़ रही है। प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। योजना के माध्यम से अब तक 28 किस्तों में कुल 18,165.19 करोड़ रुपये लाभार्थी महिलाओं के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव बन रही है।

•आर्थिक सहायता से बढ़ा आत्मविश्वास: नारायणपुर जिले के ग्राम गोहाड़ा की श्रीमती गंडाय वडडे के लिए यह योजना जीवन में खुशहाली लेकर आई है। सीमित आय वाले परिवार में बच्चों की पढ़ाई, राशन और दैनिक जरूरतों को पूरा करना उनके लिए कठिन था। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। अब वे घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ परिवार के आर्थिक निर्णयों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

•दूरस्थ अंचलों तक पहुंचा सशक्तिकरण: सुकमा जिले के ग्राम पंचायत बंडा के आश्रित गांव उसकेवाया की श्रीमती हूंगी माड़वी के जीवन में भी इस योजना ने सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मजदूरी कर परिवार चलाने वाली हूंगी के लिए हर महीने मिलने वाली सहायता राशि कठिन समय में बड़ी राहत बन गई है। अब वे बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, राशन और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर पा रही हैं। दूरस्थ और पहुंचविहीन क्षेत्र में रहने वाली श्रीमती हूंगी के लिए यह योजना आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत साबित हुई है।

•स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर: महतारी वंदन योजना महिलाओं को केवल सहायता राशि प्रदान नहीं कर रही, बल्कि उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का माध्यम भी बन रही है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड के ग्राम मझगंवा की श्रीमती हेमा सिंह ने योजना से प्राप्त राशि को बचत और निवेश में लगाया। उन्होंने एक छोटा किराना स्टोर शुरू किया, जो आज परिवार की आय का स्थायी स्रोत बन चुका है।सरगुजा जिला के ग्राम रामनगर की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की श्रीमती करियो ने योजना की राशि से बकरी पालन शुरू किया। आज यह गतिविधि उनके परिवार की आजीविका का मजबूत आधार बन गई है और उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। वहीं मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम झाफल की श्रीमती गौरी राजपूत इस राशि का उपयोग अपनी शिक्षा के लिए कर रही हैं। उनके लिए यह योजना सपनों को साकार करने का माध्यम बन गई है।

•निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सम्मान में वृद्धि: योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव महिलाओं के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि के रूप में सामने आया है। महिलाएं अब इस राशि का उपयोग शिक्षा, स्वरोजगार, पशुपालन, बचत और पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति में कर रही हैं। इससे न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और सम्मान भी बढ़ा है।

•महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महिला सशक्तिकरण को राज्य के समग्र विकास का आधार माना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे इसका लाभ प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। आज महतारी वंदन योजना केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान प्रदान करने वाला व्यापक सामाजिक परिवर्तन अभियान बन चुकी है। गंडाय वडडे, हूंगी माड़वी, हेमा सिंह, करियो और गौरी राजपूत जैसी हजारों महिलाओं की प्रेरक कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि जब सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तब वे समाज में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन की आधारशिला बनती हैं। निस्संदेह, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की धारा प्रवाहित कर रही है तथा प्रदेश के समावेशी और संतुलित विकास की मजबूत आधारशिला सिद्ध हो रही है।

HUDCO ने पूरे भारत में उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया



सरोज वार्ता/ब्यूरो

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने देशभर में अपने सभी ऑफिसों में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय (भारत सरकार) ने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी , आद्या कौशलम ट्रस्ट और समर्पण सेवा ट्रस्ट के सहयोग से नई दिल्ली के HUDCO प्लेस स्थित अंसल प्लाज़ा पार्क में किया था। इस कार्यक्रम में CMD श्री संजय कुलश्रेष्ठ, DCP श्री एम. नागराज, डायरेक्टर (फाइनेंस) श्री दलजीत सिंह खत्री और CVO श्री विनीत गुप्ता शामिल हुए। उन्होंने योग सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेकर कर्मचारियों को प्रेरित किया और जीवनशैली के तौर पर योग को अपनाने के महत्व को फिर से रेखांकित किया। इस साल की थीम 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' के अनुरूप, कर्मचारियों ने शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। HUDCO के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो स्वास्थ्य और वेलनेस के प्रति संगठन की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। देश भर में लगभग 500 कर्मचारियों ने योग दिवस की गतिविधियों में भाग लिया, जिससे एक स्वस्थ और समावेशी कार्य-संस्कृति को बढ़ावा देने पर HUDCO का लगातार ध्यान केंद्रित होने का पता चलता है। ऐसी पहलों के माध्यम से, HUDCO समग्र कल्याण को बढ़ावा देने और टिकाऊ तौर-तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है, जो उसके कर्मचारियों की कुल भलाई में योगदान करते हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने MSME की वृद्धि और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए SIDBI की प्रमुख पहलें शुरू कीं

सिडबी (SIDBI) के 37वें स्थापना दिवस का समारोह



सरोज वार्ता/ब्यूरो

मुंबई में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया के 37वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वस्थ सेक्टर भारत की विकास यात्रा, रोज़गार पैदा करने और एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। वित्त मंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति से प्रभावित सेक्टरों के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी ज़िक्र किया, जिसमें ECLGS 5.0 भी शामिल है, जो मुश्किल समय में MSME की मदद करेगा। वित्त मंत्री ने SIDBI के लिए विज़न और मार्केट-मेकर के तौर पर इसकी भूमिका के बारे में भी बताया, खासकर भारत सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के संदर्भ में। इस मौके पर, वित्त मंत्री ने MSME इकोसिस्टम को मज़बूत करने, आखिरी छोर तक क्रेडिट पहुँचाने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण को तेज़ी देने के लिए कई रणनीतिक पोर्टल/पहल भी शुरू किए। इस इवेंट के दौरान कई नई पहल और पोर्टल लॉन्च किए गए, जैसे SIDBI RRB को-लेंडिंग पोर्टल। यह SIDBI और रीजनल रूरल बैंकों के बीच पार्टनरशिप को चालू करने का एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में क्रेडिट का फ्लो बेहतर होगा। साथ ही, SIDBI MachFin Mart (www.machinerypor-tal.sidbi.in) भी लॉन्च किया गया, यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो MSMEs को एक व्यवस्थित मार्केटप्लेस के ज़रिए मशीनें हासिल करने में मदद करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म कीमत तय करने, स्टैंडर्डाइज़ेशन, टेक्नोलॉजी अपनाने और लोन मंजूरी की सुविधा देता है। इसके अलावा, MoRE (ग्रामीण उद्यमों का आधुनिकीकरण) पहल भी शुरू की गई, जिसका मकसद अगले 3 सालों में 10,000 ग्रामीण माइक्रो और कारीगर इकाइयों को बड़े बदलाव के लिए मदद देना है। यह मदद ऐसे ग्रामीण/कारीगर क्लस्टरों में क्लस्टर-आधारित उपायों के ज़रिए दी जाएगी। इवेंट में भारत सरकार के DFS का 'माइक्रो उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड' प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। उद्यम-रजिस्टर्ड माइक्रो उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की लिमिट वाले ये क्रेडिट कार्ड इस मकसद से बनाए गए हैं ताकि उन्हें आसान शर्तों और तेज़ प्रोसेस के ज़रिए अपनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों के लिए क्रेडिट मिल सके। इस मौके पर SIDBI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनोज मित्तल ने कहा कि ये पहल डिजिटल सुविधाओं और पार्टनरशिप के ज़रिए MSME फाइनेंसिंग में बदलाव लाने की SIDBI की लगातार कोशिशों में एक अहम कदम हैं। हमारा ध्यान डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपसी पार्टनरशिप के ज़रिए क्रेडिट तक पहुँच बेहतर बनाने, क्रेडिट देने की क्षमता बढ़ाने और टेक्नोलॉजी को अपनाने को बढ़ावा देने पर है। हमारा तरीका ग्रामीण उद्यमों के आधुनिकीकरण में मदद करने पर भी केंद्रित है, ताकि वे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, प्रोडक्टिव और भविष्य के लिए तैयार हो सकें, और साथ ही समावेशी और व्यापक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सके।

रेलटेल ने 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026' मनाया और अपने सभी कार्यालयों में वेलनेस और स्वस्थ उम्र बढ़ने (हेल्दी एजिंग) को बढ़ावा दिया

सरोज वार्ता/ब्यूरो



रेल मंत्रालय के तहत आने वाली नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने देश भर में अपने कर्मचारियों, सीनियर मैनेजमेंट और लीडरशिप टीमों की ज़बरदस्त भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह में हिस्सा लिया। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुरूप किया गया, जिसमें स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली के लिए योग के महत्व को रेखांकित किया गया।रेलटेल के विभिन्न कार्यालयों में योग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयास में विभिन्न विभागों के कर्मचारी एक साथ आए। इस कार्यक्रम में रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार, निदेशकों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जो एक स्वस्थ कार्य-संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम, 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग', ने सभी आयु वर्गों में शारीरिक जीवन शक्ति, भावनात्मक लचीलेपन और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में योग की परिवर्तनकारी भूमिका पर ज़ोर दिया। इस आयोजन ने प्रतिभागियों को स्वस्थ उम्र बढ़ने, तनाव के स्तर को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योग को नियमित अभ्यास के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सभा को संबोधित करते हुए, संजय कुमार ने बताया कि योग सिर्फ़ शारीरिक व्यायाम का एक तरीका नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा व्यापक तरीका है जो संतुलन, अनुशासन, सहनशक्ति और लंबे समय तक बनी रहने वाली सेहत को बढ़ावा देता है। उन्होंने कर्मचारियों को सलाह दी कि वे योग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यह बीमारियों से बचाव और शारीरिक व मानसिक फ़िटनेस बनाए रखने का एक ज़बरदस्त ज़रिया है।यह कार्यक्रम आज के तेज़-तर्रार और चुनौतीपूर्ण काम के माहौल में सेहत पर ध्यान देने वाली पहलों के बढ़ते महत्व की याद दिलाता है। गाइडेड योग सेशन और जागरूकता गतिविधियों के ज़रिए, कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे लंबे समय तक प्रोडक्टिविटी, खुशी और बेहतर सेहत बनी रहे। इंटरनेशनल डे ऑफ़ योगा 2026 में रेलटेल की भागीदारी कर्मचारियों की भलाई और संगठन की सेहत के प्रति उसकी व्यापक प्रतिबद्धता को दिखाती है। माइंडफ़ुलनेस, तनाव प्रबंधन और बीमारियों से बचाव को बढ़ावा देकर, कंपनी एक स्वस्थ और मज़बूत वर्कफ़ोर्स बनाने के राष्ट्रीय प्रयासों में अपना सहयोग जारी रखे हुए है।

डीएमआरसी ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर काम शुरू किया

सरोज वार्ता/ब्यूरो

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह स्टेशन पांचवें चरण (ए) के अंतर्गत मौजूदा मैजेंटा लाइन के विस्तार के रूप में जनकपुरी पश्चिम से आर के आश्रम मार्ग तक विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल, सचिव मोहुआ और दिल्ली मेट्रो रेल निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन एक ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा, जहां नया मैजेंटा लाइन स्टेशन मौजूदा येलो लाइन और वायलेट लाइन से निर्बाध रूप से जुड़ जाएगा। यह विशिष्ट सुविधा सरकारी कर्मचारियों और लुटियंस जोन तथा आसपास के प्रशासनिक जिलों में आने-जाने वाले यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। यह कॉरिडोर 9.913 किलोमीटर लंबा है। इसमें नौ भूमिगत स्टेशन हैं, जिनके नाम हैं: शिवाजी स्टेडियम, युग युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, युद्ध स्मारक-उच्च न्यायालय, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ। यह



परियोजना नई दिल्ली के केंद्र तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रमुख सरकारी कार्यालयों, न्यायिक संस्थानों, राष्ट्रीय स्मारकों और सम्मेलन स्थलों तक सुगम पहुंच प्रदान करती है, साथ ही समग्र नेटवर्क दक्षता और यात्री सुविधा को बढ़ाती है।

एनएमडीसी के वरिष्ठ प्रबंधन ने कर्नाटक स्थित दोणिमलै परिसर में डिजिटलीकरण, क्षमता विस्तार और सुस्थिर खनन पहलों की समीक्षा की



सरोज वार्ता/ब्यूरो

एनएमडीसी के वरिष्ठ प्रबंधन ने दोणिमलै कॉम्प्लेक्स की हाल ही में हुई एक यात्रा के दौरान परिचालन दक्षता को मजबूत करने, जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने और कर्मचारियों तथा आसपास के समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से कई रणनीतिक पहलों की समीक्षा की। इस दौरे से प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने का अवसर मिला, जो दोणिमलै को भविष्य के लिए तैयार खनन परिसर में बदलने में मदद कर रही है। साथ ही, एनएमडीसी को भारत के सबसे बड़े और जिम्मेदार लौह अयस्क उत्पादक के रूप में सुस्थापित करती है। इस यात्रा के दौरान प्रबंधन ने कुमारस्वामी खदान से 10 एमटीपीए और दोणिमलै परिसर से 17 एमटीपीए के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से चल रही क्षमता-विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास की पहलों की समीक्षा की । इन पहलों से एनएमडीसी के 100 एमटीपीए खनन कंपनी बनने के विजन में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। प्रबंधन ने 35% तक स्वद्व युक्त लौह अयस्क, लौह अयस्क स्लाइम्स और निम्न श्रेणी के लौह-युक्त पदार्थों जैसे बैंडेड हेमेटाइट जैस्पर (बीएचजे) और बैंडेड हेमेटाइट क्वार्ट्जाइट (बीएचक्यू) के उपयोग के लिए पहलों की भी समीक्षा की। परंपरागत रूप से, इन संसाधनों का सीमित उपयोग किया जाता था और मूल्यवान लौह सामग्री होने के बावजूद इन्हें अपशिष्ट के रूप में माना जाता था । लाभकारी और वैज्ञानिक खनिज प्रसंस्करण के माध्यम से, एनएमडीसी इन कम उपयोग किए गए संसाधनों को मूल्यवान कच्चे माल में बदल रहा है, मौजूदा खदानों से अधिक लौह अयस्क को पुनः प्राप्त कर रहा है, जबकि अपशिष्ट उत्पादन को कम कर रहा है । यह पहल खनन की सुस्थिर प्रथाओं का समर्थन करती है, खनिज संरक्षण में सुधार करती है, खनन कार्यों के पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करती है और भारत के इस्पात क्षेत्र की कच्ची सामग्री की बढ़ती आवश्यकताओं में योगदान करती है ।कुमारस्वामी खदान में नई लागू की गई स्वचालित गेट प्रबंधन प्रणाली दौरे के दौरान समीक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु था । डिजिटल प्रणाली ने रियल टाइम निगरानी और सामग्री की आवाजाही के सत्यापन को सक्षम बनाकर लौह अयस्क प्रेषण में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत बनाया है। यह पहल यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि खनिज संसाधनों को उनके इच्छित गंतव्यों तक सुरक्षित रूप से पहुँचाया जाए, साथ ही मैनुअल हस्तक्षेप को कम किया जाए और परिचालन संबंधी निगरानी में सुधार लाया जाए। एनएमडीसी के सीएमडी श्री अमिताभ मुखर्जी ने कार्यपालक निदेशकों के साथ मिलकर हाल ही में विकसित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिनमें हाई-राइज टावर शामिल हैं, जो कर्मचारी कल्याण और सामुदायिक विकास के प्रति एनएमडीसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है । भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक के रूप में, एनएमडीसी का मानना है कि सतत विकास उत्पादन लक्ष्यों से परे होता है और इसमें कर्मचारियों के लिए बेहतर जीवन-स्तर बनाना, स्थानीय समुदायों का समर्थन करना और पर्यावरण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित रखना शामिल है। इस अवसर पर बोलते हुए, एनएमडीसी के सीएमडी श्री अमिताभ मुखर्जी ने कहा, 'हमारा दृष्टिकोण ऐसे खनन संचालन का निर्माण करना है, जिस पर भावी पीढ़िया गर्व कर सकें । भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक के रूप में, हम दोणिमलै को एक मॉडल खनन परिसर बनाने की आकांक्षा रखते हैं, जो जिम्मेदार खनन, नवाचार और कर्मचारी कल्याण के उच्चतम मानकों को दर्शाता है । जैसे-जैसे एनएमडीसी अपने 100 एमटीपीए विजन की ओर बढ़ रहा है, हम भारत के इस्पात उद्योग को उच्च-गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । साथ ही, हम प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से हर संसाधन के मूल्य को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यहां तक कि निम्न श्रेणी के अयस्क को उत्पादक परिसंपत्तियों में बदल रहे हैं, साथ ही सुस्थिर और जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।

आरईसीपीडीसीएल ने कारगिल के विकास के लिए सीएसआर के तहत 1.25 करोड़ की सहायता प्रदान की



सरोज वार्ता/ब्यूरो

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जो आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रतिबद्धता के अंतर्गत लद्दाख के कारगिल जिला प्रशासन को ?1.25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस सहायता का उद्देश्य जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, जिससे कारगिल के लगभग 1.95 लाख निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इस समावेशी विकास पहल के अंतर्गत 19 जून, 2026 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई, जब 40-सीटर स्कूल बस को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने बस को रवाना किया। कार्यक्रम में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ट्रांसमिशन), आरईसीपीडीसीएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रिंस धवन तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), कारगिल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दुर्गम एवं भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में विद्यार्थियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नई स्कूल बस संचालित की गई है। इससे दूरदराज़ क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित होगी तथा उनके शैक्षणिक भविष्य को नई दिशा मिलेगी। यह अवसंरचनात्मक सहयोग दूरस्थ एवं वंचित समुदायों को सतत एवं प्रभावी विकास के माध्यम से सशक्त बनाने की आरईसीपीडीसीएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कंपनी का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ कर समावेशी एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना है।

लोक भवन, भुवनेश्वर में 485 किलोवाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन



सरोज वार्ता/ब्यूरो

सौर परियोजना, फैलाना आर-पार लगभग 39,000 वर्ग. फुट. अंदर लोक भवन कैंपस, है गया इंस्टॉल किया आर-पार आठ स्थानों शामिल राज्यपाल घर इमारत, प्रशासनिक इमारत, अभिषेक भोज बड़ा कमरा, ऊर्जा पार्क और वगैरह.. लैस साथ विकसित सौर तकनीकी, इंस्टालेशन है अपेक्षित को उत्पन्न लगभग 60,000 इकाइयां का साफ बिजली प्रत्येक महीना, काफी कमी पारंपरिक ऊर्जा उपभोग और कार्बन उत्सर्जन। रखना में दिमाग मौजूदा ऊर्जा कमी कारण पश्चिम एशिया टकराव, ज़रूरत को पदोन्नति करना अक्षय ऊर्जा प्रयोग है का महान महत्व। ईवी वाहनों कर सकना भी होना आरोप लगाया कारण को इंस्टालेशन का सौर पौधा। एनबीसीसी खड़ा प्रतिबद्ध को कार्यरत में को बढ़ावा प्रयोग का अक्षय ऊर्जा और करेगा भी होना कार्यरत पर हवा ऊर्जा पीढ़ी जैसा ए भाग का इसका प्रयास को बढ़ाना भारत का ऊर्जा सुरक्षा। परियोजना दर्शाता एनबीसीसी का प्रतिबद्धता को सहायक भारत का साफ ऊर्जा संक्रमण और बनाना पर्यावरणीय टिकाऊ जनता आधारभूत संरचना। पहल है अपेक्षित को योगदान देना काफी हद तक की ओर कमी कार्बन पदचिह्न का लोक भवन जटिल जबकि की सेवा जैसा ए नमूना के लिए अक्षय ऊर्जा दत्तक ग्रहण में सरकार प्रतिष्ठान। जैसा ए अग्रणी जनता क्षेत्र निर्माण और परियोजना प्रबंध कंपनी, एनबीसीसी है लगातार इनकॉरपोरेटेड टिकाऊ विशेषताएँ ऐसा जैसा सौर ऊर्जा प्रणालियाँ, बारिश का पानी कटाई, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और कुशल ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में इसका प्रमुख परियोजनाओं कौन हैं गृह या आईजीबीसी प्रमाणित। ओडिशा अवशेष एक का एनबीसीसी का चाबी केंद्र राज्यों। ऊपर साल, कंपनी है निष्पादित/निष्पादित हो रहा है अनेक प्रतिष्ठित परियोजनाओं में राज्य, शामिल आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईएम संबलपुर, राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय कटक, रावेनशॉ विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का ओडिशा, इस्पात डाक स्नातक संस्था × बहुत अच्छा स्पेशलिटी अस्पताल, राउरकेला, पवित्र मोहन प्रधान चिकित्सा कॉलेज × अस्पताल, तालचर, कौशल विकास संस्था खुर्दा, और बहुत स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाएँ। इन परियोजनाओं पास होना मजबूत शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल और नागरिक आधारभूत संरचना आर-पार राज्य जबकि उत्पादक रोज़गार अवसर और योगदान को आर्थिक विकास।

फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' दे रहा जिम्मेदारी और दृढ़ता का संदेश, डा. ऑर्थो दे रहा हर कदम को मजबूती

फिल्म 'गवर्नर' के साथ आयुर्वेदिक 'डा. ऑर्थो' की विशेष बांड साझेदारी

सरोज वार्ता/ब्यूरो

चिन्मय डी. मांडलेकर के निर्देशन में बनी फिल्म 'गवर्नर : द साइलेंट सेवियर' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म यह दर्शाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने और लोगों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी है। फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने एक प्रमोशन के दौरान डा. ऑर्थो बारे कहा कि चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है और ऐसे मजबूत कदमों के लिए चाहिए डा. ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर एवं शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई ऊर्जा, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डा. ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वहीं, फिल्म 'गवर्नर : द साइलेंट सेवियर' की रिलीज पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर डा. संजीव जुनेजा ने कहा कि आज के समय में ऐसी फिल्मों की आवश्यकता है, जो केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि दर्शकों को सकारात्मक सोच और प्रेरणा भी दें। उन्होंने फिल्म की टीम को बधाई देते हुए इसकी शानदार सफलता की कामना की। इस अवसर पर कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि डा. ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर एवं शूज को पैरों की बेहतर देखभाल और आराम को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यह उत्पाद दैनिक जीवन में पैरों को आराम प्रदान करने के साथ-साथ सक्रिय और ऊर्जावान जीवनशैली को बढ़ावा देने में सहायक है।



महाराष्ट्र की 912 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन परियोजना को मिली गति

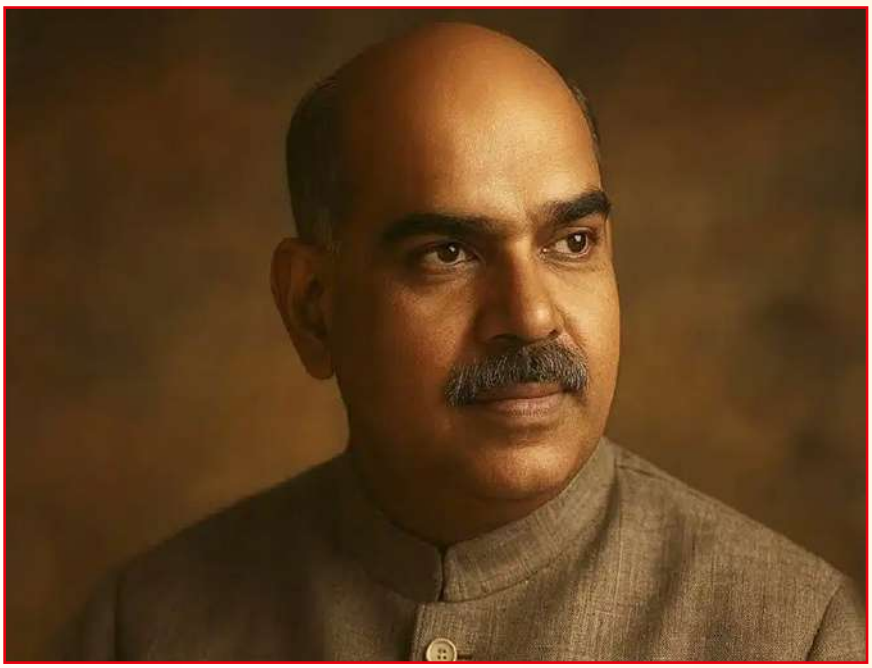


सरोज वार्ता/ब्यूरो

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जो विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में महारत्न सीपीएसयू, आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने 12 जून 2026 को सफल बोली लगाने वाले, मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को, प्रोजेक्ट के लिए खास स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी), जालना पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को सौंप दिया। महाराष्ट्र की इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन परियोजना को बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर आधार पर विकसित करने के लिए, बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर आरईसीपीडीसीएल द्वारा आयोजित टैरिफ-बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया में मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड सफल बोलीदाता रही। श्री रत्नेश कुमार (महाप्रबंधक-इंजीनियरिंग, आरईसीपीडीसीएल) ने सुश्री विनीता श्रीवानी (कंपनी सचिव) और श्री अमित नाइक (मुख्य अभियंता-टीबीसीबी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड) को एसपीवी सौंपा। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र एसटीयू और आरईसीपीडीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस प्रोजेक्ट में मोटे तौर पर जालना में 400/132 kV का सबस्टेशन और जालना (न्यू) से जालना MIDC, जालना (न्यू) से परतुर, और जालना से घनसावंगी और उटवाड़ तक लगभग 135 km 132 kV डबल-सर्किट ट्रांसमिशन लाइनें बनाना और उससे जुड़े काम शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट 24 महीनों में पूरा होने वाला है और इसकी अनुमानित लागत 912 करोड़ रुपये है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
राष्ट्रचेतना के अमर पुरोधा

सरोज वार्ता



कुछ व्यक्तित्व समय की धारा में केवल जीवित नहीं रहते, वे स्वयं इतिहास की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। उनके विचार युगों तक समाज का मार्गदर्शन करते हैं, उनका साहस पीढ़ियों को प्रेरणा देता है और उनका जीवन राष्ट्र की चेतना में सदैव स्पंदित होता रहता है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही एक विलक्षण राष्ट्रपुरुष थे, जिन्होंने अपने चिंतन, कर्म और बलिदान से भारत की राष्ट्रीय अस्मिता को नया स्वर प्रदान किया। व्यक्ति का जीवन सीमित हो सकता है, किंतु राष्ट्र के लिए जिया गया जीवन कालजयी हो जाता है। डॉ. मुखर्जी का जीवन इसी सत्य का अनुपम उदाहरण है। 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में जन्मे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी शिक्षा जगत की एक प्रतिष्ठित विभूति थे, जिनसे उन्हें विद्वता, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां अद्वितीय थीं। मात्र 33 वर्ष की आयु में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। यह उपलब्धि केवल उनकी प्रतिभा का प्रमाण नहीं थी, बल्कि भारतीय शिक्षा जगत में उनके दूरदर्शी नेतृत्व की भी पहचान थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में उन्होंने राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। वे मानते थे कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय एकता में निहित है। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा का साधन माना। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किंतु जब उन्हें लगा कि कुछ नीतियां राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं हैं, तब उन्होंने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय मंत्री पद त्यागना उचित समझा। यह उनके चरित्र की दृढ़ता और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण का प्रमाण था। वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना कर उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया वैचारिक आधार दिया। उस समय देश की राजनीति में वैचारिक स्पष्टता और राष्ट्रीय दृष्टि की आवश्यकता थी। डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव और अखंड भारत के विचार को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उनका स्पष्ट मत था कि भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है तथा इसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। जम्मू-कश्मीर के प्रश्न पर उनका संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने उस व्यवस्था का विरोध किया जिसमें एक देश के भीतर दो विधान, दो प्रधान और दो निशान की व्यवस्था लागू थी। उनका प्रसिद्ध उद्घोष- 'एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे '- आज भी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। भारत की पूर्ण एकात्मता के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। जम्मू-कश्मीर में प्रवेश के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनका यह बलिदान सदा याद रखा जाएगा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं था, बल्कि एक ऐसे विचार की अमरता का प्रारंभ था जिसने आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए कार्य करे। आज जब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब डॉ. मुखर्जी के विचार और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, सुशासन और आत्मगौरव से परिपूर्ण भारत का जो स्वप्न आज साकार होता दिखाई दे रहा है, उसकी वैचारिक नींव रखने वालों में डॉ. मुखर्जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें स्मरण करना केवल श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आत्मसात करना है जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। यह अवसर उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और भारत की अखंडता एवं गौरव को और सुदृढ़ करने का भी है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना का वह अमर स्वर हैं जो सदैव राष्ट्रभक्ति, साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देता रहेगा। उनका जीवन और बलिदान आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को यह प्रेरणा देता रहेगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और उसकी एकता, अखंडता तथा गौरव की रक्षा के लिए हर प्रकार का त्याग छोटा है।



डॉ. अर्चना गुप्ता
प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, हरियाणा

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने भारत की नौसैनिक ताकत को दी मज़बूती

आईएनएस दूनागिरी, अग्रय और संशोधक के लिए रक्षा-ग्रेड स्टील की आपूर्ति की



सरोज वार्ता/ब्यूरो

इस्पात मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और महारत्न कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के हाल ही में कमीशन किए गए तीन अत्याधुनिक जहाजों - उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट आईएनएस अग्रय, और सर्वेक्षण पोत (लार्ज) आईएनएस संशोधक के निर्माण के लिए पूरे 5,700 टन विशेष स्टील की आपूर्ति अकेले करके देश की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने में एक बार फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन तीनों उन्नत जहाजों को 21 जून, 2026 को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल (कमिशन) किया गया SAIL ने इन तीनों अत्याधुनिक जहाजों के लिए विशेष गुणवत्ता की DMR 249 ग्रेड हॉट-रोल्ड शीट और प्लेट की सप्लाई की है। कंपनी ने इस डिफेंस ग्रेड स्टील का उत्पादन और आपूर्ति अपने बोकारो, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के जरिये बेहद ही सावधानीपूर्वक किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि स्वदेश के पास देश की समुद्री सुरक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतरीन और आधुनिक तकनीकी क्षमता है। SAIL देश के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया'



अभियानों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। SAIL देश के महत्वपूर्ण नौसैनिक प्लेटफार्मों के लिए विशेष स्टील का उत्पादन करके, भारत के रक्षा स्वदेशीकरण का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। देश की रक्षा क्षेत्र की उभरती जरूरतों को देखते हुए, SAIL ने डीएमआर ग्रेड प्लेटों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अपनी प्लेट-उत्पादन सुविधाओं, विशेषकर राउरकेला स्टील प्लांट के 'स्पेशल प्लेट प्लांट' में पहले से ही अतिरिक्त पहल लागू किए हैं। यह रणनीतिक कदम रक्षा-ग्रेड स्टील के क्षेत्र में भारत के बढ़ते आयात प्रतिस्थापन में साफ दिखाई देता है। SAIL के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड में ऐतिहासिक स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत के साथ-साथ विशिष्ट प्रोजेक्ट 17 स्टील्थ फ्रिगेट्स - आईएनएस नीलगिरि, आईएनएस हिमगिरि और आईएनएस उदयगिरि के लिए स्टील की आपूर्ति शामिल है। इसके अलावा, SAIL का विशेष स्टील आईएनएस अजय, आईएनएस निस्तार और आईएनएस अंजदीप जैसे शक्तिशाली जहाजों की रीढ़ है। इन उन्नत युद्धपोतों का सफल समावेश भारत की समुद्री संप्रभुता और क्षमताओं में एक निर्णायक मील का पत्थर है। SAIL अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अशोक कुमार पंडा ने कहा, 'भारत के रक्षा क्षेत्र के एक प्रमुख भागीदार के रूप में, स्वदेश की आत्मनिर्भरता की जरूरतों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कंपनी ने पहले से ही रक्षा क्षेत्र की लगातार बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, डीएमआर ग्रेड प्लेटों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर ज़ोर दिया, विशेषकर राउरकेला स्टील प्लांट के स्पेशल प्लेट प्लांट पर ध्यान केंद्रित किया है। इन उच्च-क्षमता वाली DMR 249 स्टील प्लेटों की आपूर्ति न केवल भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान करती है, बल्कि SAIL की अत्याधुनिक तकनीकी विशेषज्ञता को भी प्रमाणित करती है।

आईआईएफसीएल की मजबूती और सतत विस्तार से भारत के अवसंरचना विकास को नई रफ्तार

सरोज वार्ता/ब्यूरो



इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री रोहित ऋषि ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की घोषणा की, जो बुनियादी ढांचा वित्तपोषण गतिविधियों में निरंतर वृद्धि, ऋण पोर्टफोलियो के निरंतर विस्तार, मजबूत परिचालन प्रदर्शन और परिसंपत्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण मजबूती को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान IIFCL का प्रदर्शन इसके निरंतर संस्थागत सुदृढ़ीकरण, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा वित्तपोषण संस्थान के रूप में बढ़ते आकार को दर्शाता है। कंपनी भारत की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई है और लचीलेपन और निरंतर व्यापार विस्तार के माध्यम से राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के विकास की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अब तक की सबसे अधिक स्वीकृतियाँ: अवसंरचना वित्तपोषण में बढ़ती भूमिका

IIFCL ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 57,680 करोड़ की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक स्वीकृतियाँ दर्ज कीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% की वृद्धि दर्शाती हैं। वार्षिक संवितरण में पिछले वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर

32,972 करोड़ हो गया, जो देश भर में अवसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में निरंतर गति को दर्शाता है।

31 मार्च, 2026 तक कंपनी का संचयी संवितरण लगभग 1.89 लाख करोड़ तक पहुँच गया। समेकित आधार पर, संवितरण ?2.14 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जो भारत के अवसंरचना विस्तार के वित्तपोषण में IIFCL के बढ़ते योगदान को रेखांकित करता है। 31 मार्च, 2026 तक IIFCL का स्टैंडअलोन ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर 81,715 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में लगभग 17% की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने संतुलित और विविध पोर्टफोलियो बनाए रखते हुए अवसंरचना क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करके अवसंरचना वित्तपोषण में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ किया है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और भारत के अवसंरचना परिदृश्य में उभरते अवसरों के अनुरूप है। मुख्य परिचालन प्रदर्शन लचीला और विस्तार योग्य बना हुआ है। IIFCL ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अपने प्रमुख वित्तीय परिचालनों में निरंतर मजबूती प्रदर्शित की। कंपनी की परिचालन आय पिछले पांच वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 3,618 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 6,972 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान परिचालन लाभ में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 1,168 करोड़ से बढ़कर 2,197 करोड़ हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 1,984 करोड़ का कर-पूर्व लाभ और 1,379 करोड़ का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया। बढ़ी हुई शुद्ध संपत्ति और विवेकपूर्ण पूंजी प्रबंधन से विकास क्षमता को मजबूती मिलती है। वित्त वर्ष 2025-26 में IIFCL की शुद्ध संपत्ति पिछले वर्ष के 16,395 करोड़ से बढ़कर 17,898 करोड़ हो गई, जो कंपनी के पूंजी आधार और ऋण देने की क्षमता में निरंतर मजबूती को दर्शाती है। 31 मार्च, 2026 तक IIFCL ने पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात 20.53% बनाए रखा - जो नियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर है। यह मजबूत पूंजी स्थिति भारत की अवसंरचना वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में कंपनी के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और दीर्घकालिक लचीलेपन को रेखांकित करती है। प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक श्री रोहित ऋषि ने कहाः 'वित्त वर्ष 2025-26 आईआईएफसीएल के लिए मजबूत परिचालन प्रगति और संस्थागत सुदृढ़ीकरण का एक और वर्ष है। हमारे रिकॉर्ड स्तर पर स्वीकृत ऋण, ऋण पुस्तिका में निरंतर विस्तार, निवल मूल्य, सुदृढ़ परिचालन प्रदर्शन और परिसंपत्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हमारे मुख्य वित्तपोषण व्यवसाय और हमारी दीर्घकालिक रणनीतिक दिशा की मजबूती को दर्शाते हैं। एसआईएफटीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के बाद, आईआईएफसीएल को अधिक वित्तपोषण लचीलेपन और विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं में व्यापक भागीदारी के माध्यम से मजबूत वृद्धि देखने की उम्मीद है। इस महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव से नए और अभिनव ऋण उत्पादों के माध्यम से तेजी से ऋण विस्तार संभव हो पाता है। जैसे-जैसे भारत अवसंरचना-आधारित आर्थिक विकास के परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश कर रहा है, आईआईएफसीएल जिम्मेदार, अभिनव और टिकाऊ वित्तपोषण समाधानों के माध्यम से राष्ट्र की विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक मजबूत और बढ़ती हुई बैलेंस शीट, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढांचा और बढ़ती क्षेत्रीय उपस्थिति के साथ, कंपनी भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना वित्तपोषण संस्थान के रूप में विकास के अपने अगले चरण के लिए अच्छी स्थिति में है। '

सानोज कुमार झा ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला

सरोज वार्ता/संवाददाता

कोयला मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी, IAS अधिकारी सानोज कुमार झा ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। यह नियुक्ति नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ के लिए लीडरशिप में एक अहम बदलाव है, जो माइनिंग, थर्मल पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना पर काम कर रही है। एक सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अधिकारी के तौर पर, झा के पास कोयला और ऊर्जा सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन का लंबा अनुभव और गहरी जानकारी है। पॉलिसी बनाने, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और गवर्नेंस में उनके मज़बूत अनुभव से एनएलसी इंडिया लिमिटेड के एक ऐसी डायवर्सिफाइड एनर्जी कंपनी बनने की प्रक्रिया को और मज़बूती मिलने की उम्मीद है, जिसकी पारंपरिक और क्लीन एनर्जी बिज़नेस में मौजूदगी



बढ़ रही है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, कर्मचारियों और स्टेकहोल्डर्स ने झा का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्हें भरोसा है कि झा की लीडरशिप कंपनी को ऑपरेशनल एक्सीलेंस, सस्टेनेबल ग्रोथ और लंबे समय में वैल्यू बनाने के ऊँचे स्टैंडर्ड्स तक पहुँचने में मदद करेगी। उनकी देखरेख में, एनएलसी इंडिया लिमिटेड से उम्मीद है कि वह क्षमता बढ़ाने, कामकाज को बेहतर बनाने, डिजिटल बदलाव, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और नए उभरते सेक्टर में कदम रखने जैसे रणनीतिक कामों में तेज़ी लाएगी। ये प्राथमिकताएं कंपनी के उस लंबे समय के विज़न से मेल खाती हैं, जिसका मकसद भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ने में मदद करना है। झा ने यह अतिरिक्त ज़िम्मेदारी ऐसे समय में संभाली है जब एनएलसी इंडिया लिमिटेड देश भर में कई बड़े पैमाने के माइनिंग, बिजली उत्पादन और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप से कंपनी को रणनीतिक दिशा मिलेगी, क्योंकि यह PSU अपने विकास के रोडमैप पर आगे बढ़ रही है और भारत के सस्टेनेबल एनर्जी भविष्य में अपना योगदान मज़बूत कर रही है।

इंडियन ऑयल के उत्तरी क्षेत्र ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छता रथ' के साथ 'स्वच्छता पखवाड़ा 2026' की शुरुआत की

सरोज वार्ता/संवाददाता

इंडियनऑयल के नॉर्दर्न रीजन और दिल्ली स्टेट ऑफिस ने 'स्वच्छता पखवाड़ा 2026' लॉन्च किया। यह 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाला दो हफ़्ते का सफ़ाई अभियान है, जो स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण की स्थिरता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।इस कैंपेन की शुरुआत नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के असिस्टेंट डायरेक्टर शैलेश कुमार और इंडियनऑयल के नॉर्दर्न रीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दिल्ली स्टेट ऑफिस के स्टेट हेड हेमंत राठौर ने 'स्वच्छता शपथ' दिलाकर की। इस शपथ के ज़रिए स्वच्छता और ज़िम्मेदार नागरिक व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया।इस लॉन्च के हिस्से के तौर पर, गणमान्य व्यक्तियों ने नई दिल्ली के ग्रीन पार्क से 'स्वच्छता रथ' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहर भर में घूमकर स्वच्छता, साफ़-सफ़ाई, कचरा प्रबंधन और सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएगा। यह जागरूकता कैंपेन लोगों तक पहुँचने वाले कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए नागरिकों को शामिल करेगा और साफ़-सफ़ाई बनाए रखने तथा पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार आदतें अपनाने में



समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देगा।पर्यावरण संरक्षण के संदेश को मज़बूत करने के लिए, गणमान्य व्यक्तियों ने पौधे भी लगाए और बांटे। उन्होंने स्वच्छता की पहलों के साथ-साथ हरियाली बढ़ाने और टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देने के महत्व पर ज़ोर दिया। हेमंत राठौर ने कर्मचारियों और स्टेकहोल्डर्स से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी व सामूहिक प्रयासों के ज़रिए 'स्वच्छ भारत' के विज़न को साकार करने में योगदान दें।'स्वच्छता पखवाड़ा' पहल पर्यावरण की देखभाल, समुदाय के साथ जुड़ाव और टिकाऊ विकास के प्रति इंडियनऑयल की लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के भारत सरकार के देशव्यापी प्रयासों के अनुरूप है।जागरूकता अभियानों, व्यवहार में बदलाव लाने वाले कार्यक्रमों और कर्मचारियों की भागीदारी के ज़रिए, इंडियनऑयल का लक्ष्य साफ़-सुथरे शहर बनाने, प्लास्टिक कचरा कम करने और एक स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में लोगों की भागीदारी को मज़बूत करना है।



जानलेवा मैनहोल

सरोज वार्ता/ब्यूरो

मानसून की बारिश जहां किसानों के लिये राहत लेकर आती हैं, वहीं तंत्र की काहिली और भ्रष्टाचार की पोल भी खोल देती है। मानसून की शुरुआती बारिश ने एक बार फिर सार्वजनिक संरचनाओं की जानलेवा खामियों को ही उजागर किया। मुंबई में बारिश के पानी में नजर न आने वाले एक खुले मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हाल ही में खुले बहुचर्चित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली उजागर कर दी। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि बारिश के मौसम में स्थानीय निकायों की लापरवाही व खराब इंजीनियरिंग के चलते कैसे लोगों का जीवन जोखिम में पड़ जाता है। निस्संदेह, मुंबई में हुए हादसे को रोका जा सकता था। कथित साफ-सफाई के बाद लापरवाही से खुला छोड़ा गया मैनहोल तब जानलेवा बन गया, जब बारिश के पानी से ढका खुला मैनहोल नजर नहीं आया। निस्संदेह, दुर्घटना के बाद अधिकारियों को निलंबित करना और ठेकेदार को काली सूची में डालना, फौरी तौर पर सही कदम है, लेकिन सवाल यह है कि हादसे होने के बाद ही ऐसे कदम क्यों उठाये जाते हैं? पहले से ही नागरिकों की सुरक्षा के लिये चाक-चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं होती? कायदे से किसी सड़क पर मैनहोल खोलने से पहले बैरिकेड्स लगाने, चेतावनी देने वाले संकेत और अस्थायी कवर से ढकना बुनियादी सुरक्षा उपाय हैं। जिन्हें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बीते साल भी दिल्ली में भारी बारिश के दौरान स्कूटर फिसलने से एक महिला और उसका तीन साल का बेटा पानी से भरे नाले में बह गये थे। ये असुरक्षित ड्रेनेज संरचना की घातकता को ही दर्शाता है। विडंबना है कि हमारा तंत्र सालभर सोया रहता है और जब बरसात शुरू होने को होती है, तब मरम्मत- नालों की सफाई के काम की औपचारिकता पूरी करता है। निस्संदेह, संबंधित विभागों के अधिकारियों की सर्वकालिक जवाबदेही तय की जानी चाहिए। फिर किसी भी तरह की लापरवाही होने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के धंसने की घटना भी एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है। यह निर्विवाद सत्य है कि कोई सड़क बारिश आने के कारण रातों-रात नहीं धंसती है। इसमें सड़क निर्माण के दौरान सतर्कता की अनदेखी भी शामिल है। दरअसल, सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी की कारगर व्यवस्था न होने, मिट्टी की स्थिरता सुनिश्चित न करने और निर्माण में गुणवत्ता की कमी से ही बरसाती पानी सड़क की सतह के नीचे मिट्टी को धीरे-धीरे काटने लगता है। कालांतर यह मिट्टी का कटाव ही सड़क धंसने की वजह बन जाता है। साल 2024 में बिहार में पुलों के ढहने की शृंखला ने भी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग की हकीकत बतायी थी। इसी तरह की चिंताएं अकसर सामने आती हैं जब आधुनिक कहे जाने वाले महानगरों बेंगलुरू और मुंबई में हर मानसून में सड़कों में बने गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं इससे यातायात में भी अराजकता व व्यवधान पैदा होता है। बहरहाल, इन सभी घटनाओं के मूल में एक बात तो समान है कि स्थानीय निकाय व प्रशासन जोखिमों का समय रहते अनुमान नहीं लगा पाते हैं। यह तथ्य सभी अधिकारी जानते हैं कि एक निश्चित समय पर मानसून आता है। बाकायदा समय-समय पर सूचना माध्यमों में मौसम विभाग द्वारा मानसून की भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन अधिकारी तब जागते हैं जब स्थितियां जटिल हो जाती हैं। वे इन हालातों को अप्रत्याशित आपात स्थिति के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। दरअसल,कई स्तरों पर होने वाली कमीशनखोरी व राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अकसर ठेकेदारों की जवाबदेही तय नहीं की जाती है।

•विडंबना यह भी है कि निरीक्षण भी अक्सर खानापूर्ति जैसा ही होता है। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक संरचना का रखरखाव भी निवारक के बजाय प्रतिक्रियात्मक ही रहता है। वास्तव में कारगर समाधान के लिये जरूरी है कि मानसून से पहले सुरक्षा उपायों को संस्थागत ढंग से सुनिश्चित किया जाए, इंजीनियरिंग मानकों को सख्ती से लागू किया जाए, गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच हो और ठेकेदार को कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जाए। दुर्घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय यह सुनिश्चित हो कि ऐसी घटनाएं हो ही न पाएं।



नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप

हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन पर विशेष नीति समर्थन की पैरवी

सरोज वार्ता/ब्यूरो

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में राज्य के विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित भारत-2047 के संकल्प का आधार हमारी मानव पूंजी है। इसी सोच के अनुरूप उत्तराखंड सरकार मानव संसाधन विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष बल दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभिक बाल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लासरूम तथा कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों में भी शोध, नवाचार एवं उद्यमिता को नई दिशा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि युवाओं को रोजगार प्राप्त करने वाले के बजाय रोजगार सृजित करने वाला बनाया जा सके।

युवाओं को स्किल देने पर जोर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में देवभूमि उद्यमिता विकास योजना, स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम, उद्योग-अकादमिक सहयोग तथा आईटीआई संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने जैसी पहल लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड' के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए विगत वर्षों में 30 से अधिक विभिन्न नई नीतियों के माध्यम से कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सेवा क्षेत्र को एकीकृत करते हुए विकास के एक समन्वित मॉडल के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था, निवेश, रोजगार एवं प्रति व्यक्ति आय में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

उत्तराखंड को राष्ट्रीय मॉडल बनाने का प्रयास: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती, बागवानी, औषधीय पौधों, योग एवं वेलनेस, पर्यटन और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को भविष्य के विकास इंजन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। साथ ही उत्तराखंड को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, वेलनेस इकोनॉमी तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को देश की पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन एवं संवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त है। हिमालय, गंगा, यमुना एवं विशाल वन क्षेत्र केवल उत्तराखंड की ही धरोहर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं। इसीलिए हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण, आपदा प्रबंधन, कार्बन न्यूट्रैलिटी, ग्रीन एनर्जी एवं पर्वतीय अवसंरचना विकास से जुड़े विषयों पर विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था पर विचार करना वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

सुशासन और तकनीकी नवाचार : उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने सुशासन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहल प्रारम्भ की हैं। देवभूमि परिवार पहचान योजना, खनन क्षेत्र में डिजिटल निगरानी प्रणाली, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया का ऑनलाइन सरलीकरण तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े सुधारों ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। इसी तरह उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। पीरूल आधारित ऊर्जा उत्पादन जैसे नवाचार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विश्व की अग्रणी शक्तियों में अपना स्थान और अधिक सुदृढ़ करने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड भी इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता, ऊर्जा और सामर्थ्य के साथ योगदान देता रहेगा।

कुंभ और नंदा राजजात का निमंत्रण :



मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 12 वर्ष के रिकॉर्ड कार्यकाल पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सर्वाधिक अवधि तक जनादेश प्राप्त कर निरंतर राष्ट्रसेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री सहित नीति आयोग के सभी सदस्यों को उत्तराखंड में अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुम्भ मेला और नन्दा राजजात यात्रा का निमंत्रण दिया।

पीएफसी और आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा विलय योजना को मंजूरी

सरोज वार्ता/ब्यूरो

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत, आरईसी (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) का पीएफसी (हस्तांतरिती कंपनी) में विलय की योजना (स्कीम) को मंजूरी दी। आरईसी का पीएफसी में विलय होने से एक ऐसी वित्तपोषण इकाई बनेगी जिसका कुल ऋण पोर्टफोलियो 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। यह योजना कई शर्तों पर निर्भर है, जिनमें लागू कानूनों के तहत ज़रूरी सभी मंजूरियां और सहमतियां शामिल हैं। इनमें दोनों कंपनियों के शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स की मंजूरी, और सभी संबंधित रेगुलेटरी और सरकारी अथॉरिटीज़ की मंजूरी शामिल है। साथ ही, मर्जर के बाद बनी कंपनी का 'कंपनीज़ एक्ट, 2013' के तहत 'सरकारी कंपनी' का दर्जा बना रहना चाहिए और भारत सरकार के पास विलय के बाद बनी कंपनी में बहुमत वोटिंग अधिकार और कंट्रोल (सीधे या परोक्ष रूप से) बना रहना चाहिए। योजना और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, आरईसी का पीएफसी में प्रस्तावित विलय होने पर, आरईसी

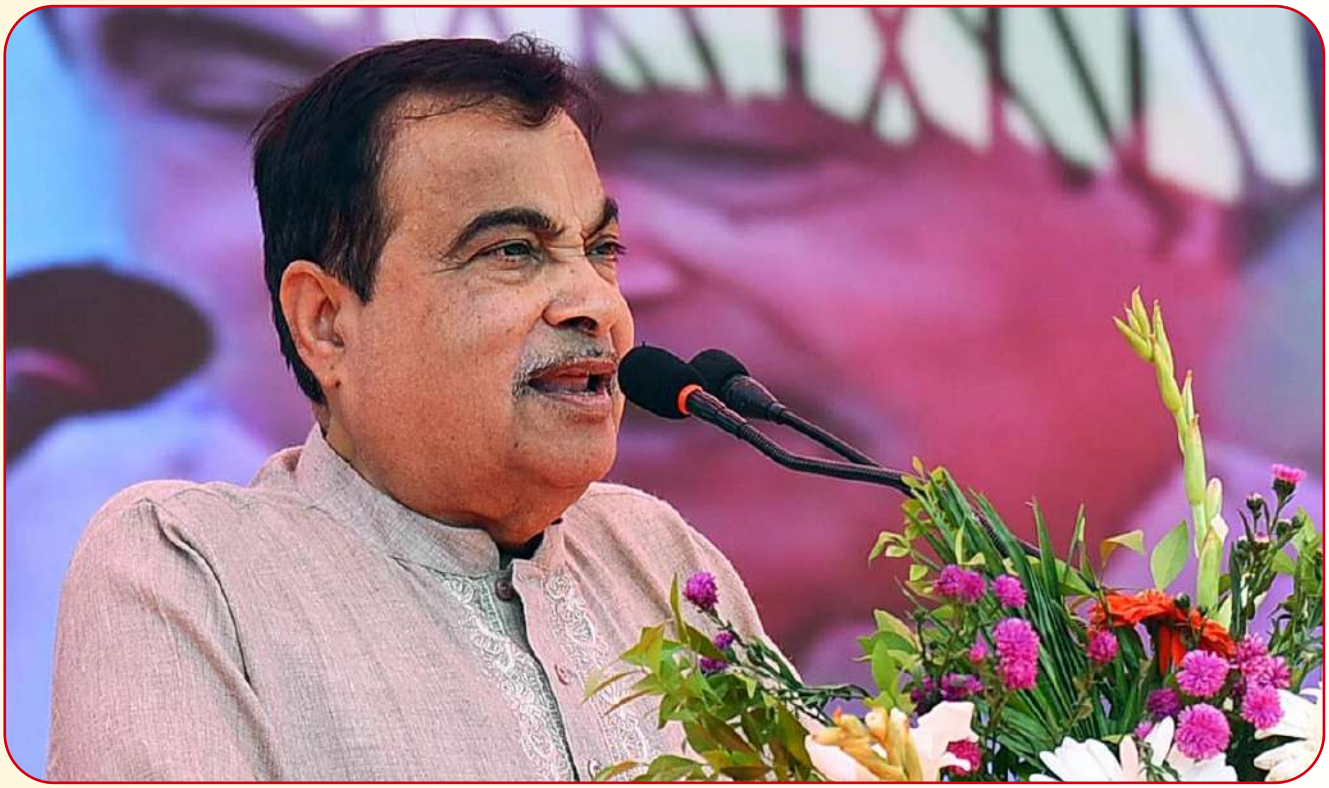


के शेयरधारकों को, रिकॉर्ड तिथि पर, आरईसी के हर 100 इक्विटी शेयरों (प्रत्येक INR 10/- मूल्य के) के बदले पीएफसी के 88 इक्विटी शेयर (प्रत्येक INR 10/- मूल्य के) जारी किए जाएंगे। रिकॉर्ड तिथि का निर्धारण पीएफसी और आरईसी के बोर्ड द्वारा भविष्य में किया जाएगा।

सलाहकार

डेलॉयट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी, पीएफसी और आरईसी दोनों के लिए लेनदेन और कर सलाहकार के रूप में कार्य कर रही है और सिरिल अमरचंद मंगलदास कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए पीएफसी द्वारा आरबीएसए वैल्यूएशन एडवाइजर्स एलएलपी और आरईसी द्वारा अर्न्स्ट एंड यंग मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ एलएलपी को नियुक्त किया गया था। संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट पर अपनी-अपनी निष्पक्ष राय प्रदान करने के लिए पीएफसी द्वारा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और आरईसी द्वारा नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट को नियुक्त किया गया था।

क्या नितिन गडकरी की ई20 नीति की वजह से खराब हो रही हैं गाड़ियां?



ललित गर्ग

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर इन दिनों चौतरफा हमले हो रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ई20 पेट्रोल को वाहनों की खराबी का कारण बताया जा रहा है, तो कभी सड़कों पर उतरने की चेतावनी देकर केंद्र सरकार की एथनॉल नीति के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो लंबे समय से एथनॉल मिश्रित ईंधन को भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम बताते रहे हैं, अब उसी नीति को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में हैं। हम आपको बता दें कि ई20 यानी पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथनॉल मिश्रण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ताजा मामले में बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपनी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में आई खराबी का आरोप सीधे ई20 पेट्रोल और सरकार की नीति पर लगाया है। मनीष का दावा है कि उनकी दो महीने पुरानी और लगभग 12 हजार किलोमीटर चली गाड़ी का इंजन अचानक खराब हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्यूल टैंक से निकाले गए पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथनॉल और अशुद्धियां मिलीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह काफी भावुक नजर आए और बोले कि लाखों रुपये खर्च कर खरीदी गई गाड़ी इतनी जल्दी खराब हो जाना गंभीर चिंता का विषय है। देखा जाये तो मनीष कश्यप अकेले नहीं हैं। देशभर में हजारों वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन परफॉर्मेंस कम होने और वाहनों में तकनीकी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। कई वीडियो में गुलाबी रंग का पेट्रोल, टंकी में पानी जैसी परत और अन्य अशुद्धियां दिखाकर दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक है। हालांकि सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय इन दावों को खारिज कर रहे हैं। इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक रूप भी ले लिया है। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ई20 नीति के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। 'टीम भारत अगेंस्ट द एथनॉल स्कैम' के बैनर तले प्रस्तावित इस प्रदर्शन को एथनॉल नीति के खिलाफ पहला बड़ा सार्वजनिक आंदोलन बताया जा रहा है। पूनावाला का कहना है कि लोग एथनॉल नीति के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसकी जल्दबाजी में की गई क्रियान्वयन प्रक्रिया और उपभोक्ताओं को विकल्प न दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो कुछ लोग नितिन गडकरी के आवास के बाहर धरने पर बैठ सकते हैं। देखा जाये तो विवाद केवल वाहन खराबी तक सीमित नहीं है। एक उद्योगपति ने भी सरकार की ई20 नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि सरकार जनता के सामने इस योजना को पूरी तरह सफल बता रही है, लेकिन अदालत में इसे अभी भी 'चल रहा प्रयोग' बताया गया। हालांकि बाद में अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस दावे को गलत बताया। वहीं उक्त उद्योगपति का कहना है कि असली चिंता उन उद्योगों और निवेशकों की है जिन्होंने सरकार की नीति पर भरोसा करके एथनॉल संयंत्रों में अरबों रुपये का निवेश किया। यदि एथनॉल की खरीद और मांग ही निश्चित नहीं है, तो निवेशकों को किस भरोसे निवेश के लिए प्रेरित किया गया। हम आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश से जुड़ा था, जिसमें एथनॉल आवंटन प्रक्रिया को दोबारा खोलने की बात कही गई थी। इस सुनवाई के दौरान यह भी सवाल उठा कि सरकार द्वारा एथनॉल खरीद की बाध्यता

वास्तव में कितनी मजबूत है। आलोचकों का कहना है कि यदि खरीद केवल 'सर्वश्रेष्ठ प्रयास' के आधार पर होगी तो उद्योगों की वित्तीय स्थिरता पर खतरा पैदा हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने एथनॉल नीति के आर्थिक और कृषि प्रभावों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ई20 कार्यक्रम भारत को विदेशी मक्के और उससे बने उत्पादों पर अधिक निर्भर बना सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी आरोप लगाया है कि यह नीति अब किसान केंद्रित कम और आयात आधारित ढांचे जैसी अधिक दिखाई देने लगी है। उन्होंने सरकार से ई20 की अनिवार्यता पर पुनर्विचार कर ई5 या ई10 जैसे विकल्प फिर से उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं देशी और विदेशी वाहन निर्माता कंपनियों ने ई20 पेट्रोल को लेकर मिश्रित लेकिन संतुलित रुख अपनाया है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, होंडा और किआ जैसी कंपनियों ने कहा है कि अप्रैल 2023 के बाद बने अधिकांश नए वाहन ई20 अनुकूल बनाए जा चुके हैं और उनमें इस ईंधन के इस्तेमाल से कोई बड़ा सुरक्षा खतरा नहीं है। वाहन उद्योग संगठन सियाम ने भी माना है कि ई20 से माइलेज में लगभग 2 से 4 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे स्थायी इंजन क्षति का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वहीं महिंद्रा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि ई20 सुरक्षित तो है, लेकिन इससे परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ सकता है। टोयोटा सहित कई कंपनियों ने अपने नए पेट्रोल मॉडलों को ई20 अनुकूल घोषित किया है, जबकि कुछ विशेषज्ञों और कंपनियों ने पुराने वाहनों में सावधानी बरतने

● मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, होंडा और किआ जैसी कंपनियों ने कहा है कि अप्रैल 2023 के बाद बने अधिकांश नए वाहन ई20 अनुकूल बनाए जा चुके हैं और उनमें इस ईंधन के इस्तेमाल से कोई बड़ा सुरक्षा खतरा नहीं है। वाहन उद्योग संगठन सियाम ने भी माना है कि ई20 से माइलेज में लगभग 2 से 4 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे स्थायी इंजन क्षति का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वहीं महिंद्रा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि ई20 सुरक्षित तो है, लेकिन इससे परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ सकता है। टोयोटा सहित कई कंपनियों ने अपने नए पेट्रोल मॉडलों को ई20 अनुकूल घोषित किया है, जबकि कुछ विशेषज्ञों और कंपनियों ने पुराने वाहनों में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

की सलाह दी है। दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार इस योजना का बचाव कर रही है। सरकार का दावा है कि भारत ने निर्धारित समय से पहले दिसंबर 2025 में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम से देश को 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत हुई, किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारी कमी आई। सरकार का कहना है कि इससे 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का विकल्प तैयार हुआ। सरकार का यह भी कहना है कि वाहन कंपनियों और सियाम के साथ व्यापक चर्चा के बाद ही ई20 लागू किया गया और कई निर्माता वर्ष 2009 से ही ई20 अनुकूल इंजन विकसित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी माइलेज घटने के दावों को मामूली बताया है। उनका कहना है कि एथनॉल मिश्रित ईंधन से इंजन की नॉकिंग कम होती है और वाहन की गति क्षमता बेहतर होती है। वहीं नितिन गडकरी ने एथनॉल विरोधी प्रचार को 'पेड कैंपेन' करार दिया है। उनका आरोप है कि पेट्रोलियम लॉबी भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने से परेशान है और इसलिए दुष्प्रचार कर रही है। गडकरी ने यह चुनौती भी दी कि दुनिया में कोई एक उदाहरण दिखाया जाए जहां ई20 पेट्रोल से वाहन स्थायी रूप से खराब हुए हों। बहरहाल, फिलहाल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। एक ओर सरकार इसे किसानों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो दूसरी ओर उपभोक्ता, वाहन मालिक और कुछ उद्योग विशेषज्ञ इसके प्रभावों को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। आने वाले समय में यह बहस केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़कों, अदालतों और राजनीतिक मंचों तक और तेज होती दिखाई दे सकती है।



नजर आ रहे खतरे से बचाव नहीं, भूकंप से कैसे बचाएंगी सरकारें



- योगेन्द्र योगी

वेनेजुएला में एक मिनट के अंदर दो बड़े विनाशकारी भूकंप में करीब दो हजार लोगों की मौत हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 10 हजार लोग घायल हो गए। बगैर किसी चेतावनी के आने वाली भूकंप जैसी आपदाएं सरकारों को चेताती हैं कि पहले से बचाव के उपाए किए जाएं, ताकि कम से कम जानमाल का नुकसान हो सकें। भूकंप का खतरा भारत मे भी है। देश के कई हिस्सों में कई बार शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। सवाल यह है कि पूर्व में आए इन भूकंपों से देश की सरकारों ने कोई सबक सीखा है। क्या देश में ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि भूकंप आने पर कम से कम जानमाल का नुकसान हो। दरअसल भारत के राजनीतिक दलों और सरकारों से किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले और बाद में बचाव की ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। कारण साफ है केंद्र और राज्यों की सरकारों को सामने स्पष्ट नजर आते हुए खतरों से लोगों को बचाने का कोई इंतजाम नहीं हो, वे भूकंप जैसे छिपे हुए खतरों से कैसे बचाएंगे। दिल्ली के बाद लखनउ में आग से 15 लोगों की मौत हो गई। ऐसी लाखों इमारतें अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें आग से बचाने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। जब दिल्ली में आग लगी तभी राज्यों की सरकारों को सतर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन सरकारों ने लोगों की जान की परवाह नहीं की। अगले ही दिन

> ● भूकंप संभावित क्षेत्रों में ज़ोन-1 में भूकंप आने की आशंका सबसे कम रहती है, वहीं ज़ोन-5 में ज़्यादा प्रबल रहती है। दिल्ली-एनसीआर का इलाक़ा सीस्मिक ज़ोन-4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सीस्मिक गतिविधियाँ तेज़ रहती हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों ने भारत के क़रीब 59% भू-भाग को भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में आग ने पांच-छह मरीजों को लील लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा और फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में आग ने फ्लैट और शोरूम खाक कर दिए। तीन दिन में आग की चार भयानक घटनाओं ने लोगों को डरा दिया है और करीब 26 लोगों की जलकर या काले धुएं की चपेट में आकर मौत हो गई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनुमानों के अनुसार, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों के 60 प्रतिशत से अधिक छोटे और मध्यम भवन बिना वैध फायर एनओसी के चल रहे हैं। देश भर में दमकल केंद्रों में 97.5 प्रतिशत, दमकल कर्मियों में 96.2 प्रतिशत और अग्निशमन उपकरणों में लगभग 80 प्रतिशत तक की कमी है। देश के लगभग हर बड़े शहर में सुरक्षा नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। यह खतरा ऐसा है, जो साफ दिखाई देता है। इससे बचाव के शत-प्रतिशत इंतजाम भी किए जा सकते हैं। इसके बावजूद राज्यों और केंद्र ने पूर्व में हुए ऐसे हादसों से सबक नहीं सीखा। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है, सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे खतरे से निपटने में सरकारें नाकाम हैं तो भूंकप जैसी अचानक आने वाली आपदा और उसके भयावह रूप से सरकारें कैसे निपटेंगी। जबकि भूगर्भ वैज्ञानिक साफ चेता चुके हैं कि देश के कितने हिस्सों में कभी भी भीषण भूकंप आ सकता है। पिछले दो दशकों में देश में 10 बड़े भूकंप आए हैं, जिनमें 20,000 से अधिक लोगों की जान गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी के मुताबिक भारत में करीब 20 करोड़ इमारतें भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में आती हैं। इनमें से कई इमारतें 30-40 साल पहले बनी थीं और इनमें से कई इमारतें नेशनल बिल्डिंग कोड्स का पालन नहीं करती हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में ज़ोन-1 में भूकंप आने की आशंका सबसे कम रहती है, वहीं ज़ोन-5 में ज़्यादा प्रबल रहती है। दिल्ली-एनसीआर का इलाक़ा सीस्मिक ज़ोन-4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सीस्मिक गतिविधियाँ तेज़ रहती हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों

ने भारत के क़रीब 59% भू-भाग को भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। जानकार सीस्मिक ज़ोन-4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज़्यादा बताते हैं। ग़ौरतलब है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर सीस्मिक ज़ोन-3 की श्रेणी में आते हैं। जबकि भूगर्भशास्त्री कहते हैं कि दिल्ली की दुविधा यह भी है कि वह हिमालय के निकट है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टॉनिक प्लेटों के मिलने से बना था और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। नेशनल सेंटर फोर सिसमोलॉजी के मुताबिक भारत के 29 शहरों पर भूकंप का गंभीर ख़तरा है। इन शहरों में दिल्ली समेत नौ राज्यों की राजधानियां भी हैं। ये ज़्यादातर शहर हिमालय ज़ोन से लगे हैं। हिमालय से लगे शहर दुनियां के उन शहरों में शुमार हैं, जहां भूकंप का सबसे ज़्यादा ख़तरा रहता है। दिल्ली, पटना, श्रीनगर, कोहिमा, पुडुच्चेरी, गुवाहाटी, गंगटोक, शिमला, देहरादून, इम्फाल और चंडीगढ़ भूकंपीय क्षेत्र के ज़ोन चार और पांच में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस (आईआईएससी) के मुताबिक ये वो शहर हैं जहां आबादी का घनत्व बहुत सघन है और ये गंगा के मैदानी भाग हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि सिस्मिक जोन-4 में आने वाली राजधानी दिल्ली भूकंप के बड़े झटके से खासा प्रभावित हो सकती है। अगर यहां 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो दिल्ली की कई सारी इमारतें और घर रेत की तरह भरभराकर गिर जाएंगे। ऐसा इसलिए है, क्योंकि दिल्ली की इमारतों में इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री ऐसी है, जो भूकंप के झटकों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। दिल्ली में मकान बनाने की निर्माण सामग्री ही

● अग्नि दुर्घटनाओं की तरह तो नहीं पर मौटे तौर पर सरकारों को इस बात का अंदाजा है कि देश के किन इलाकों में भूकंप आ सकता है। जिस देश में साफ नजर आने वाले खतरे की नेताओं और सरकारों को परवाह नहीं, उन्हें छिपे हुए अचानक आने वाले खतरों से देश के लोगों को बचाने की क्या परवाह होगी। देश में ऐसा एक भी राज्य नहीं हैं, जहां की किसी भी तरह की इमरातें, अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षित हो, या उनमें अग्नि दुर्घटना होने पर बचाव के पूरे कानूनी प्रावधान हों, ऐसे में छिपे हुए अचानक आए खतरनाक भूकंप से बचाने के लिए इंतजाम भगवान भरोसे है।

आफत की सबसे बड़ी वजह है। दिल्ली में 1760 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इन अनधिकृत कॉलोनियों में गैर-इंजीनियरिंग इमारतें बनी हैं, जिनमें भूकंप प्रतिरोध क्षमता शायद ही हो। भूकंप के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील और खतरनाक माने जाने वाले ज़ोन पांच में भारत का पूरा पूर्वोत्तर है। इनमें जम्मू-कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के साथ उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर का कुछ हिस्सा, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र का कुछ भाग ज़ोन चार में हैं। गुजरात का भुज 2001 में भयावह तरीक़े से भूकंप की चपेट में आया था। इस भूकंप में 20 हज़ार लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में आदेश दिया था कि ऐसी सभी इमारतें, जिनमें 100 या उससे अधिक लोग रहते हैं, उनके ऊपर भूकंप-रोधी होने वाली किसी एक श्रेणी का साफ़ उल्लेख होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अन्य जनहित के आदेशों की तरह सरकारी फाइलों में दफन हो गया। अग्नि दुर्घटनाओं की तरह तो नहीं पर मौटे तौर पर सरकारों को इस बात का अंदाजा है कि देश के किन इलाकों में भूकंप आ सकता है। जिस देश में साफ नजर आने वाले खतरे की नेताओं और सरकारों को परवाह नहीं, उन्हें छिपे हुए अचानक आने वाले खतरों से देश के लोगों को बचाने की क्या परवाह होगी। देश में ऐसा एक भी राज्य नहीं हैं, जहां की किसी भी तरह की इमरातें, अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षित हो, या उनमें अग्नि दुर्घटना होने पर बचाव के पूरे कानूनी प्रावधान हों, ऐसे में छिपे हुए अचानक आए खतरनाक भूकंप से बचाने के लिए इंतजाम भगवान भरोसे है। होना तो यह चाहिए था कि इतने अग्निकांडों के बाद देश में सरकारों की नींद खुल जानी चाहिए थी। देश के जितने भी व्यवसायिक या निजी इमारतें हैं, उनमें आग से बचाव के इंतजामों की तत्काल जांच की जानी चाहिए थी। आग लगने पर लोगों की जान खतरे में डालने वाले ऐसे भवनों को तत्काल सील किया जाना चाहिए था। इससे भी महत्वपूर्ण जिन विभागों की अग्निशमन के उपायों की जांच करने की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। एक के बाद एक अग्नि दुर्घटनाएं होती रहीं किन्तु सरकारों की नींद नही खुली।



बच्ची पर हैवानियत का कहर



सरोज वार्ता/ब्यूरो

अब आए दिन देश के प्रिंट मीडिया से लेकर अन्य सूचना माध्यमों में यौन अपराधों की विचलित करने वाली घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं। यौन लिप्साओं का यह विस्फोट विचलित करने वाला है। कोई निर्भया, किसी के साहस के बूते अपने साथ हुए अन्याय को उजागर कर देती है, वहीं देश की अनेक निर्भयाएं यौन हिंसा व क्रूरता के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में त्रास झेलने को अभिशप्त हो जाती हैं। हाल की दो घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारह वर्षीय बालिका को चार दिन बंधक बनाकर दो दर्जन लोगों द्वारा दुराचार किया गया। इस मामले में 18 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। दूसरी घटना पश्चिम बंगाल की है जहां बारुईपुर में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। शव परीक्षण में पाया गया कि उसके सिर व निजी अंगों पर गंभीर चोटें थी। इतना ही नहीं, दुराचार के बाद उसे बोरे मे बंद करके जिंदा ही तालाब में डुबो दिया गया। दोनों ही घटनाएं विचलित करने वाली हैं, लेकिन श्रीगंगानगर की घटना हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली है। जनाक्रोश के चलते प्रशासन ने न केवल 18 लोगों को गिरफ्तार किया बल्कि उन होटलों को भी ध्वस्त किया गया जहां अलग-अलग जगहों में बच्ची को बंधक बनाकर देह व्यापार कराया गया। निस्संदेह, मोबाइल के बढ़ते हस्तक्षेप से परिवार संस्था की चूलें हिली नजर आती हैं। कथित सोशल मीडिया समाज में विद्रूपताओं को जन्म दे रहा है। श्रीगंगानगर की बारह वर्षीय लड़की शहर से सौ किमी दूर अपने एक इंस्टाग्राम फ्रेंड से मिलने जाती है, जो उससे वहां दुराचार करता है। वहां से देर रात शहर लौटने पर एक रिक्शेवाले के झांसे में आकर होटल पहुंचती है और फिर उसके साथ दुराचार का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। परिजनों के लापता किशोरी के तलाश में थाने पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आती हैं, फिर उसे मुक्त कराया जाता है। निस्संदेह, ये घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। इस राक्षसी कृत्य से उद्वेलित लोग श्रीगंगानगर की सड़कों पर उतर आए। क्षुब्ध लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर कानून के रखवालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जनाक्रोश को देखते हुए 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह कि भारतीय समाज में हो रहे यौन लिप्साओं के विस्फोट की वजह क्या है? ये नैतिक पतन की पराकाष्ठा क्यों हो रही है? हवस के भूखे भेड़िए न उम्र देखते हैं, न किसी बेटी की बेबसी। उस किशोरी के साथ हुई बर्बरता के बारे में सोचकर भी रूह कांपती है। जो शायद ही जीवनभर इस त्रासदी से उबर पाये। कहीं न कहीं इंटरनेट व सोशल मीडिया पर यौन स्वच्छंदता की पश्चिम की आंधी हमारे समाज को पतित कर रही है। हमारे परंपरागत शुचिता के रिश्तों को तार-तार करके निरंकुश यौन व्यवहार को तार्किक बताने की साजिश रची जा रही है। हम बच्चों को रामराज के संस्कार देते हैं, जबकि समाज में दानवराज का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। बच्चों को भी त्याग-तपस्या से लालन-पालन करने वाले मां-बाप की बजाय आभासी दुनिया के छद्म मित्र रास आ रहे हैं। जिसके सम्मोहन में यह किशोरी घर से निकली और उसका पहला शिकार बनी। हवस के भेड़िये भी परिस्थितियों की मारी लड़कियों को ही अपने शिकंजे में लेते हैं। ऐसे में बेटियों को भी घर से निकलते वक्त समय की संवेदनशीलता और लोगों की विश्वसनीयता को परखना चाहिए। घर वालों से चोरी-छिपे अनजान लोगों पर यकीन करने की वजह से अकसर बेटियां अपराधियों की आसान शिकार बनती हैं। यौन अपराधों के उफान के दौर में पुलिस और स्त्री रक्षा से जुड़ी एजेंसियों को भी नये दौर की नई चुनौतियों के मुताबिक तैयार करना होगा। इसमें चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ी संस्थाओं की सजगता -सक्रियता बढ़ाने तथा पॉक्सो व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को सख्त बनाने की जरूरत है। अभिभावक व स्कूल-कालेज बच्चियों को यौन-हिंसा से बचने और आत्मरक्षा से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा करें। यदि इस दिशा में गंभीर पहल नहीं हुई तो पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर लगाए जा रहे 'रेप कैपिटल' के आरोप हकीकत समझे जाने लगेंगे।

•बच्चों को भी त्याग-तपस्या से लालन-पालन करने वाले मां-बाप की बजाय आभासी दुनिया के छद्म मित्र रास आ रहे हैं। जिसके सम्मोहन में यह किशोरी घर से निकली और उसका पहला शिकार बनी। हवस के भेड़िये भी परिस्थितियों की मारी लड़कियों को ही अपने शिकंजे में लेते हैं। ऐसे में बेटियों को भी घर से निकलते वक्त समय की संवेदनशीलता और लोगों की विश्वसनीयता को परखना चाहिए।

पारदर्शिता हेतु कठोर फैसले लेने से न चूके ट्रस्ट



सरोज वार्ता/ब्यूरो

देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था-विश्वास को आहत करने वाला चंदा-चोरी प्रकरण सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में आखिरकार महामंत्री चंपत राय व सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। अब ट्रस्ट के अन्य सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री बनाया गया है। राममंदिर के चंदे में हेरफेर से उठे देशव्यापी विवाद के बाद प्राथमिकी दर्ज होने, एसआईटी के गठन और कुछ गिरफ्तारियों के बाद ये इस्तीफे अपरिहार्य थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ दो इस्तीफों से श्रद्धालुओं के भरोसे की बहाली हो पाएगी? जैसा कि नवनियुक्त अंतरिम महामंत्री कृष्ण मोहन ने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि चंदा चोरी के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा,उसे कड़ी सजा मिले। उन्होंने स्वीकारा कि ट्रस्ट प्रबंधन और संचालन में कहीं न कहीं खामियां रही हैं। उन्हें दूर करने का प्रयास होगा। साथ ही माना कि जो तथ्य सामने आए हैं उससे न्यास की छवि धूमिल हुई है। एक अविश्वास का भाव उत्पन्न हुआ। ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को फिर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा में शामिल होने से पहले कुछ सालों तक परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु वैज्ञानिक भी रहे हैं। वे दलित समुदाय से आते हैं। वे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने सोमवार को अयोध्या में उन बहुमूल्य वस्तुओं को मीडिया के सामने प्रदर्शित किया, जिनके गायब होने को लेकर अटकलें लगायी जा रही थीं। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के संचालन के लिये विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक बाईस जुलाई को होगी। जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिये जाने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि तब तक चंदा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आस्था व विश्वास से खिलवाड़ के कृत्य की जांच के लिये क्या एसआईटी की जांच पर्याप्त है? क्या चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मात्र से उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदार व्यवहार पर कार्रवाई पूरी मान ली जाए? क्या इतनी कार्रवाई मात्र से सारे प्रकरण से संदेह के बादल छंट जाएंगे और लोगों का खंडित भरोसा फिर से कायम हो जाएगा? अब तो संघ प्रमुख ने भी स्वीकारा है कि इस घटनाक्रम से व्यापक हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में अब ट्रस्ट को कठोर फैसले लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिए। निस्संदेह, समय रहते यदि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चंदा प्रकरण में संवेदनशीलता के साथ कड़ी निगाह रखी होती तो यह बड़ा विवाद न खड़ा होता। शुरुआती दौर में जब मामले की सुगबुगाहट सामने आई तो तभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने स्वाभाविक ही हैं। कुछ लोग तो ट्रस्ट को भंग करके नये सिरे से इसके गठन की बात कहते रहे हैं। बहरहाल, इतना तय है कि ट्रस्ट की कारगुजारियों में सबकुछ न तो पारदर्शी था और न ही सब कुछ नियम अनुसार ही चला। कहा जा रहा है कि कुछ पदाधिकारियों के पास जरूरत से ज्यादा अधिकार थे, जिसके चलते अन्य सदस्य उदासीन बने रहे। यही वजह है कि कुछ लोग एसआईटी से इतर एक उच्च स्तरीय जांच की मांग इस मामले में करते रहे हैं। निस्संदेह, बहुचर्चित चढ़ावा चोरी प्रकरण की गूंज पूरी दुनिया में हुई है, जिसने संघ,भाजपा, केंद्र सरकार व प्रदेश की सरकार को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। यही वजह है कि लोग इस मामले में किसी लीपा-पोती के बजाय भक्तों के दान की पारदर्शी व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। जिससे गाहे-बगाहे देश के अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों में भी उठने वाले चंदे में हेरा-फेरी के मामलों का हमेशा के लिये पटाक्षेप हो सके। साथ ही श्रद्धालुओं को यह भी पता लग सके कि दान की राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

इथेनॉल का मोल



सरोज वार्ता/ब्यूरो

खाड़ी युद्ध के चलते उपजे ईंधन संकट ने भारत समेत पूरी दुनिया को सबक दिए हैं कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये नये विकल्प तलाशे जाएं। भारत जैसे देश के लिये तो यह बड़ी चुनौती है क्योंकि हम पूरी तरह कच्चे तेल व गैस के लिये विदेशी संसाधनों पर ही निर्भर हैं। जिससे संकटपूर्ण स्थितियों में न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि हमारी दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी दांव पर लगती है। ऐसे ही संकट से जूझने के लिये देश ने इथेनॉल के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया। देश में पहले ही सामान्य पेट्रोल में बीस फीसदी इथेनॉल मिलाया जा रहा है। देश में विदेशी मुद्रा की बचत व आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये ज्यादा इथेनॉल वाले ई-85 फ्यूल उपलब्ध कराया गया। लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच कई मुद्दों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। दरअसल,ये वाहन ई-85 यानी 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल तथा ई-100 यानी शुद्ध इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के लिये डिजाइन किये गए हैं। जबकि पेट्रोल से चलने वाली सामान्य गाड़ियां ई-20 यानी बीस फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल के अनुकूल होती हैं। दरअसल, चुनिंदा आउटलेट्स पर ई-85 उपलब्ध कराने का निर्णय आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मकसद से लिया गया है। यह एक हकीकत है कि आज भी देश का नब्बे फीसदी कच्चा तेल आयातित किया जा रहा है। दुनियाभर में गाहे-बगाहे

• इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि बॉयोफ्यूल इतनी जल्दी फॉसिल फ्यूल का विकल्प नहीं बन सकता। इस बाबत पर्याप्त तैयारी, पारदर्शिता और सभी हितधारकों का सहयोग लेना जरूरी है। इस मामले में जल्दबाजी करने से बचा जाना चाहिए। यदि हम सजगता व सतर्कता से आगे बढ़ते हैं तो ई-85 एक सफल मॉडल बन सकता है। अन्यथा हम एक अच्छा मौका चूक सकते हैं।

पैदा होने वाले भू-राजनीतिक संकटों ने बार-बार देश के ऊर्जा इकोसिस्टम की खामियों को ही उजागर किया है। इसमें दो राय नहीं है कि फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये इथेनॉल को मुख्य ईंधन के रूप से बढ़ावा देने का मकसद ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बढ़ना है। वहीं दूसरी ओर इसके उपयोग से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी ला सकते हैं। निश्चय ही वाहनों में इथेनॉल को बढ़ावा देना देश में आयातित कच्चे तेल के दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन इस बदलाव को सिरे चढ़ाने के लिए बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों की आशंकाएं दूर हो सकें। जरूरत लोगों का भरोसा हासिल करने की है। भारत में इथेनॉल मिले तेल के उपयोग ने इससे होने वाले तमाम फायदों को साबित किया है। इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। साथ ही देश में इथेनॉल का सशक्त उद्योग विकसित हुआ है। यदि बाजार में इथेनॉल पर लोगों का भरोसा बढ़ता है और इसकी मांग बढ़ती है तो इससे किसानों को कमाई के नये अवसर मिल सकते हैं। इथेनॉल की ज्यादा मांग होने पर गन्ने और मक्का का बाजार विस्तार लेगा। वहीं दूसरी ओर ई-85 की कीमत पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले कम रखने के फैसले से, उन उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है, जिनके पास इसके अनुकूल गाड़ियां है। भले ही इस फ्यूल की ईंधन दक्षता कम हो, लेकिन यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को संबल देगा। बहरहाल, इस उम्मीद के साथ ही, हमें हकीकत का भी ध्यान रखना है। दरअसल, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने इंजन की क्षमता, जंग लगने, ईंधन सिस्टम पर प्रभाव और इसकी दीर्घकालिक क्षमता को लेकर चिंताएं जतायी हैं। निस्संदेह, इन मुद्दों को सीधे खारिज करने के बजाय इन पर गंभीर रूप से मंथन करना चाहिए। अगर इन मुद्दों का निराकरण नहीं होता है तो भ्रम व संशय की स्थिति बनी रहेगी। जिसे अविलंब दूर करने की भी जरूरत है। इस वैकल्पिक ईंधन की सहज उपलब्धता के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व गाड़ियों को इसके अनुरूप बनाना, वैकल्पिक ईंधन की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण तथा इससे जुड़े तकनीकी प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए।

सरलता की जरूरत

सरोज वार्ता/ब्यूरो



तकनीक ने मानव जीवन की रफ्तार को अभूतपूर्व गति दी है। सुबह की चाय के डिजिटल भुगतान से लेकर हवाई टिकट और बैंकिंग तक, सब कुछ अब एक छोटी-सी स्क्रीन पर सिमट गया है। युवाओं के लिए यह सुविधा और अवसर का नया संसार है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए यही दुनिया कई बार उलझन, असुरक्षा और निर्भरता का कारण बन जाती है। अपनों से जुड़े रहने की खुशी और हर काम के डिजिटल होने की मजबूरी के बीच पुरानी पीढ़ी जिस संघर्ष से गुजर रही है, वह आज की एक बड़ी विडंबना बन गई है। स्मार्टफोन अब केवल युवाओं का उपकरण नहीं रहा। दादा-दादी वीडियो कॉल पर दूर बैठे अपने पोते-पोतियों को देखकर भावुक हो उठते हैं। व्हाट्सएप पर परिवार से जुड़े रहना, पुराने मित्रों को खोजना और यूट्यूब पर भजन सुनना उनके अकेलेपन को काफी हद तक कम करता है। लेकिन यही तकनीक कई बार उनके लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। स्क्रीन पर दर्जनों एप, लगातार आने वाले संदेश, अचानक बदली हुई सेटिंग या किसी जरूरी फाइल के मिट जाने का डर उन्हें हमेशा असहज बनाए रखता है। छोटी-सी तकनीकी चूक भी उनका आत्मविश्वास डगमगा देती है। कई बुजुर्ग इस डर से स्मार्टफोन का सीमित उपयोग करते हैं और हर नए डिजिटल काम के लिए परिवार के किसी सदस्य का इंतजार करते हैं। उनकी आत्मनिर्भरता भी प्रभावित होती है। सबसे गंभीर चिंता साइबर ठगी का बढ़ता खतरा है। डिजिटल दुनिया की सीमित समझ का फायदा उठाकर अपराधी बुजुर्गों को सबसे आसान निशाना बना रहे हैं। फर्जी बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी बनकर फोन करना अब आम बात हो गई है। 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए साइबर अपराधों में ठग वीडियो कॉल के जरिए कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर वरिष्ठ नागरिकों से लाखों-करोड़ों रुपये ठग लेते हैं। केवाईसी अपडेट, पेंशन बंद होने या बैंक खाते के सत्यापन के नाम पर ओटीपी और बैंक विवरण हासिल कर जीवनभर की जमा-पूंजी साफ कर दी जाती है। आर्थिक नुकसान उन्हें गहरा मानसिक आघात भी पहुंचाता है, जिससे कई बुजुर्ग अवसाद और असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में ठगी के बाद वे खुद को दोषी मानने लगते हैं, परिवार के सामने अपनी बात रखने से हिचकिचाते हैं। स्थिति आर्थिक ही नहीं, भावनात्मक संकट भी पैदा करती है। मगर वे इस डिजिटल व्यवस्था से दूर नहीं रह सकते। पेंशन, बैंकिंग, बिजली-पानी के बिल, सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार ऑनलाइन होती जा रही हैं। पहले पेंशनभोगी बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करते थे। अब डिजिटल जीवन प्रमाण की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ उंगलियों के निशान धुंधले पड़ जाने से कई बार सत्यापन सफल नहीं हो पाता। ऐसे में उन्हें बार-बार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

> ***डिजिटल बदलाव का एक सामाजिक पहलू भी है। संयुक्त परिवारों के टूटने और युवाओं के रोजगार हेतु बाहर जाने से बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। ऐसे में मोबाइल और इंटरनेट अनिवार्य जरूरत बन गए हैं। जब उनके सामने तकनीकी समस्या आती है, तब अकेलापन व असहायता का एहसास गहरा हो जाता है। जरूरी है कि डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में भी देखें।***

बैंकिंग भी अब पासबुक से आगे बढ़कर पासवर्ड, ओटीपी और मोबाइल एप पर निर्भर हो गई है। एक पासवर्ड भूल जाने का मतलब कई बार अपने ही पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना है। रेलवे टिकट, अस्पताल में पंजीकरण, गैस बुकिंग, बीमा, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जैसी अनेक सेवाओं में भी डिजिटल माध्यम प्रमुख हो चुका है। ऐसे में तकनीक से दूरी का अब विकल्प नहीं रह गया है। डिजिटल बदलाव का एक सामाजिक पहलू भी है। संयुक्त परिवारों के टूटने और युवाओं के रोजगार हेतु बाहर जाने से बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। ऐसे में मोबाइल और इंटरनेट अनिवार्य जरूरत बन गए हैं। जब उनके सामने तकनीकी समस्या आती है, तब अकेलापन व असहायता का एहसास गहरा हो जाता है। जरूरी है कि डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में भी देखें। निस्संदेह, तकनीक दौर में चुनौती यह है कि विकास समावेशी हो। डिजिटल सेवाओं का डिज़ाइन वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। बैंकिंग व सरकारी एप अधिक सरल हों, बड़े वित्तीय लेनदेन में अतिरिक्त मानवीय सत्यापन की व्यवस्था हो तथा साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं। बैंक, डाकघर, पंचायतें, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण शिविर लगाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ने संग, वे तकनीक का सुरक्षित उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल साक्षरता गांव व मोहल्ले तक पहुंचे। जिन माता-पिता और दादा-दादी ने कभी हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उन्हें डिजिटल दुनिया में हमारा सहारा चाहिए। उनकी हर शंका पर झल्लाने के बजाय धैर्य से समझाना होगा कि कोई बैंक या पुलिस अधिकारी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता और न ही वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी होती है। तकनीक की सफलता तभी है, जब वह हर पीढ़ी को साथ लेकर चले। आधुनिकता का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब हमारे बुजुर्ग भी डिजिटल दुनिया में सम्मान, आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ जी सकें।

दिल्ली के वायु प्रदूषण के साथ ओजोन प्रदूषण की चुनौती



ललित गर्ग

राजधानी दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण की भयावह समस्या से जूझती रही है। हर सर्दी में धुंध की मोटी चादर, जहरीली हवा और दमघोंटू वातावरण राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते हैं। अब तक इस संकट की चर्चा मुख्यतः पीएम 2.5, पीएम 10, पराली और वाहनों के धुएँ तक सीमित रही, लेकिन अब एक नया और अधिक खतरनाक खतरा तेजी से उभरकर सामने आया है-भूतलीय (ग्राउंड लेवल) ओजोन प्रदूषण। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, जयपुर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद जैसे शहर भी ओजोन प्रदूषण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके दुष्प्रभाव धीरे-धीरे मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण को भीतर तक बीमार कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को भी अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर दिया जाता है। कभी किसानों की पराली को संपूर्ण दोषी ठहरा दिया जाता है तो कभी केवल वाहनों को। जबकि

आज दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग सांस लेने में कठिनाई, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें ओजोन प्रदूषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसे निर्णय निश्चित रूप से सकारात्मक हैं।

वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक है। यदि समस्या की जड़ तक पहुँचना है तो अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, ऊर्जा उपभोग की वर्तमान व्यवस्था और विकास के मौजूदा मॉडल पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा। दिल्ली आज केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रदूषण हॉटस्पॉट भी बन चुकी है। गर्मियों में बढ़ते तापमान, तेज धूप और वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से भूतलीय ओजोन बनती है। यह वही ओजोन नहीं है जो वायुमंडल की ऊपरी परत में पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। धरातल पर बनने वाली ओजोन एक विषैली गैस है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता कम करती है, दमा के रोगियों की स्थिति बिगाड़ती है, आँखों में जलन पैदा करती है तथा हृदय रोगों का जोखिम बढ़ाती है। आज दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग सांस लेने में कठिनाई, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें ओजोन प्रदूषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसे निर्णय निश्चित रूप



से सकारात्मक हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन केवल वाहन नीति से समस्या का समाधान संभव नहीं है। वास्तविक संकट अनियोजित शहरीकरण का है। पिछले दो दशकों में दिल्ली और उससे लगे क्षेत्रों में जिस तेजी से खेत, तालाब और हरित क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में बदले हैं, उसने प्राकृतिक संतुलन को गहरा आघात पहुँचाया है। जहाँ कभी वर्षा का पानी धरती में समा जाता था, वहाँ अब सीमेंट और डामर की सतह है। पारंपरिक जलस्रोत मिट गए, पेड़ों की संख्या घटी और गर्मी बढ़ती गई। यही कारण है कि शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक रहने लगा है। यही अतिरिक्त गर्मी ओजोन बनने की प्रक्रिया को और तेज करती है। आज महानगरों का विस्तार विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है। शहरों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, आवास चाहिए, उद्योग चाहिए। इन सबके लिए खेत समाप्त हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और जलस्रोत नष्ट हो रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रदूषण केवल हवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल, मिट्टी और जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। विकास की यह दिशा अंततः मानव जीवन के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है। दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और गुणवत्ता अभी भी इतनी प्रभावी नहीं हो सकी कि लोग निजी वाहनों का त्याग करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना स्वागतयोग्य है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि बिजली यदि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से आएगी तो प्रदूषण केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित परिवहन को समानांतर गति से बढ़ाना आवश्यक है। ओजोन प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ओजोन फसलों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर उत्पादन घटा देती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मानसून और बढ़ती गर्मी पहले ही किसानों के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ओजोन प्रदूषण कृषि संकट को और गहरा कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किंतु अब समय आ गया है कि इसकी रणनीति का विस्तार किया जाए। केवल पार्टिकुलेट मैटर पर ध्यान देने के बजाय ओजोन जैसे द्वितीयक प्रदूषकों की निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रण पर भी समान बल देना होगा। वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र को अधिक व्यापक, आधुनिक और पारदर्शी बनाना होगा। समस्या के समाधान में नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कचरा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, खुले में ईंधन जलाना, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे का अनुचित निस्तारण जैसी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, साइकिल और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, हरित पट्टियों का विकास और पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन भी प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संकट भी है। बढ़ती बीमारियाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ डालती हैं, कार्यक्षमता घटाती हैं और करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि का कारण बनती हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि प्रदूषण बच्चों और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका कहीं अधिक गंभीर मूल्य चुकाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम स्वागतयोग्य हैं और उनसे सकारात्मक परिणामों की आशा की जा सकती है, किंतु यह तभी संभव होगा जब केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज मिलकर समन्वित प्रयास करें। प्रदूषण किसी एक सरकार, एक मौसम या एक कारण की समस्या नहीं है। यह हमारे विकास मॉडल, जीवनशैली और पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण का परिणाम है। आज आवश्यकता दोषारोपण की नहीं, बल्कि दूरदर्शी नीति और सामूहिक उत्तरदायित्व की है। यदि हम स्वच्छ हवा चाहते हैं तो केवल प्रदूषण कम करने की योजनाएँ नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित विकास की नई संस्कृति विकसित करनी होगी। अन्यथा ओजोन जैसी अदृश्य गैसें हमारे शहरों को धीरे-धीरे बीमार करती रहेंगी और विकास का यह मॉडल स्वयं मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा।

भाई-बहन की जोड़ी मोदी-ताकाइची ने रचा इतिहास, हिंद प्रशांत में संतुलन की नई धुरी बने भारत-जापान



नीरज कुमार दुबे

भारत और जापान ने अपने विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी संबंधों को नई मजबूती देते हुए नई दिल्ली में आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने साफ संकेत दिया कि बदलते वैश्विक हालात के बीच भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दूसरे के भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बनकर उभर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी करते हुए संबंधों को और गहरा करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची को अपनी 'छोटी बहन' बताते हुए भारत और जापान के बीच बौद्ध सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया, विशेषकर जापान के नारा प्रांत से भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव को रेखांकित किया। वहीं ताकाइची ने भी मोदी को अपना 'बड़े भाई' बताया और कहा कि दोनों देशों के संबंध अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग रहा। दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त वक्तव्य जारी किया और भारतीय तथा जापानी संस्थानों के बीच कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की सूक्ष्म तकनीकी क्षमता और भारत की साफ्टवेयर विशेषज्ञता का मेल वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास को नई दिशा देगा। यह सहयोग केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेजी से भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत और जापान ने अपने पहले संयुक्त रक्षा विकास परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली 'यूनिकॉर्न' के सह विकास से संबंधित है। इस समझौते को हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम कदम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि दोनों देश क्वॉड समूह के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। चीन की बढ़ती समुद्री आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक बदलते सामरिक समीकरणों के बीच यह रक्षा सहयोग विशेष महत्व रखता है। साथ ही भारत और जापान ने ऊर्जा सुरक्षा तथा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत

> *रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत और जापान ने अपने पहले संयुक्त रक्षा विकास परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली 'यूनिकॉर्न' के सह विकास से संबंधित है। इस समझौते को हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम कदम माना जा रहा है।*

बनाने पर भी सहमति जताई। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, धातु और उर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए साझा रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार व्यवस्था पर भी चर्चा की, जिसके तहत रुपये और येन में सीधे व्यापार की संभावना पर काम होगा। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अधिक रणनीतिक स्वायत्तता मिलेगी। साथ ही जापान ने अगले दस वर्षों में भारत में दस ट्रिलियन येन निवेश करने की घोषणा दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी की जाएगी। वर्तमान में जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल परियोजना सहित कई आधारभूत ढांचा योजनाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जापान की प्रधानमंत्री के साथ आया बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी इस बात का स्पष्ट संकेत था कि टोक्यो भारत में निवेश बढ़ाने जा रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति मिली है। औषधि, चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौतों के माध्यम से दोनों देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की व्यापक उत्पादन क्षमता और जापान की गुणवत्ता आधारित तकनीक मिलकर विश्व को सस्ती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं। इसके साथ ही भारत जापान जैव गैस पहल के अंतर्गत भारत में एक हजार जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देखा जाये तो यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है। चीन की सैन्य सक्रियता, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को लेकर बढ़ती चिंताओं ने भारत और जापान को और करीब ला दिया है। अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर उठते सवालों के बीच टोक्यो अब नई दिल्ली को अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारों में देख रहा है। भारत भी जापान को केवल निवेशक नहीं बल्कि दीर्घकालिक सामरिक सहयोगी के रूप में देख रहा है। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंधों ने भी इस साझेदारी को मजबूती दी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी की जापान यात्राओं से शुरू हुआ यह संबंध अब व्यापक सामरिक साझेदारी का रूप ले चुका है। वर्तमान वार्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत जापान संबंध एशिया की सबसे निर्णायक रणनीतिक धुरी बन सकते हैं। देखा जाये तो भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती का प्रभाव केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे एशिया और वैश्विक शक्ति संतुलन पर दिखाई देगा। लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सहयोग और सामरिक विश्वास पर आधारित यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चीन की बढ़ती आक्रामकता, वैश्विक आपूर्ति संकट और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत और जापान का साथ आना एशिया में एक नए रणनीतिक संतुलन का संकेत माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी न केवल व्यापार, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगी, बल्कि विश्व राजनीति में भी एक भरोसेमंद और स्थिर शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकती है।

● वर्तमान में जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल परियोजना सहित कई आधारभूत ढांचा योजनाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जापान की प्रधानमंत्री के साथ आया बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी इस बात का स्पष्ट संकेत था कि टोक्यो भारत में निवेश बढ़ाने जा रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति मिली है। औषधि, चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौतों के माध्यम से दोनों देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देने का संकल्प लिया है।



नागरिकता के दस्तावेजों पर इतना भ्रम ठीक नहीं..



उमेश चतुर्वेदी

पिछले कुछ वर्षों में पासपोर्ट हासिल करना आसान हो गया है। इसकी वजह तकनीकी क्रांति तो है ही, लेकिन सरकारी नीतियों ने भी आम आदमी के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया है। पासपोर्ट हासिल करने के कठिन दौर से लेकर आसानी से प्राप्त होने के मौजूदा दौर में, आम नागरिक इसे अपनी नागरिकता का एक वैध दस्तावेज मानता रहा है। लेकिन पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के पासपोर्ट को लेकर दिए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस अधिकारी के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं। जहां पासपोर्ट हासिल करने को चार धाम यात्रा जैसी उपलब्धि माना जाता रहा हो, जहां किसी व्यक्ति की पहचान के लिए मजबूत सरकारी दस्तावेज माना जाता रहा हो, वहां ऐसा बयान आएगा तो विवाद होगा ही। तो विवाद हो रहा है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट नागरिकता का वैध दस्तावेज नही है तो फिर कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता के लिए क्या सबूत पेश करे। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के शब्दों से गुजरें तो विदेश मंत्रालय के अधिकारी का कहना गलत भी नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में मतदाता सूचियों के विशेष और गहन परीक्षण के दौरान जब घोषित कर दिया गया कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना उसकी नागरिकता के सबूत नहीं है और अब पासपोर्ट भी नहीं रहा, तो फिर भारतीय नागरिक क्या करे। जरूरत पड़ने पर वह कैसे साबित करे कि वह भारतीय नागरिक है। इस आधार पर तो देश के ज्यादातर लोग अपनी नागरिकता को तो साबित ही नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज के दौर की तमाम लड़ाइयों का बुनियादी और मजबूत आधार चूंकि नैरेटिव बन गया है तो यह भी साबित करने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है। इसके लपेटे में मोदी समर्थक ताकतें भी आएंगी, भारतीय जनता पार्टी पर तो खैर सवाल उठेगा ही। इस नैरेटिव को खड़ा होने से पहले ही जरूरी है कि नागरिकता के वैध दस्तावेज को लेकर जारी भ्रम को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अन्यथा भ्रम का यह कुहासा जितना फैलेगा, वह आम नागरिक के मन में व्यवस्था के प्रति गुस्सा और क्षोभ भरेगा। इससे तनाव बढ़ाने वाली ताकतों को भी मौका मिलेगा। पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने जो कहा है, वह गलत भी नहीं है। अपने देश में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी किया जाता है। जबकि भारत में नागरिकता की व्याख्या और प्रमाणिकता के लिए भारतीय नागरिकता कानून 1955 है। पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 के मुताबिक, अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है। बस शर्त यह होगी कि सरकार को ऐसा लगे कि उसके लिए पासपोर्ट जारी करना व्यापक जनहित में जरूरी है। इस कानून से साफ है कि पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग अलग चीजें हैं। बेशक भारतीय पासपोर्ट सिर्फ भारतीयों को ही मिलता है, लेकिन यह पत्थर की लकीर जैसा नियम नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20 भारत सरकार को छूट देती है कि व्यापक जनहित में वह भारतीय नागरिक ना होने के बावजूद किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी कर सकती है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भले ही विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन पासपोर्ट के जरिए नागरिकता प्रमाणित करने के तीन अभियुक्तों समेत चार लोगों के दावे को बांबे हाईकोर्ट 2013 में ही खारिज कर चुका है। उन्होंने अपनी नागरिकता के लिए पासपोर्ट पेश किया था। बांबे हाईकोर्ट ने दो सितंबर 2013 के अपने फैसले में साफ कर दिया था कि अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है तो पासपोर्ट को अपनी नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं पेश कर सकते। वैसे आधार कार्ड का कानून भी मानता है कि आधार कार्ड सिर्फ निवास और पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आधार कानून 2016 की धारा में साफ लिखा है कि आधार कार्ड से नागरिकता की बजाय सिर्फ निवास स्थान और पहचान प्रमाणित होता है। इसकी वजह यह है कि आधार कानून के तहत 182 दिनों तक भारत में लगातार रहने वाले व्यक्ति को सरकार चाहे तो आधार कार्ड जारी कर सकती है। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय भी इसे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर चुका है। इसी तरह पैन कार्ड के लिए भी व्यवस्था दी गई है। पैन कार्ड का कानूनी आधार है कि व्यक्ति अर्जन कर रहा है और टैक्स दे रहा है। आधुनिक विश्व व्यवस्था की एक खामी यह है कि यहां कानून की भाषा अलग होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कानूनी भाषा जटिल होती है और उसके शब्द जाल को आम आदमी नहीं समझ पाता। इसी आधार पर उसकी अवधारणाएं विकसित होती हैं और फिर वह किसी विषय का व्यवस्था को लेकर अपनी राय बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी को इन जटिलताओं की समझ है, शायद यही वजह है कि उनके कार्यकाल में देश के सैकड़ों गैरजरूरी कानूनों को या तो रद्द किया गया है या फिर कुछ नए संदर्भों वाले कानूनों में समाहित कर दिया गया है। आज के दौर में नागरिकता के दस्तावेज के रूप जब पासपोर्ट, आधार कार्ड , पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को आखिरी और अंतिम प्रमाण मानने से इनकार किया जाता है तो अपनी लोक और आम धारणा के चलते आम आदमी इसके विरोध में उतर आता है। यही वजह है कि जब मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर के दौरान इन दस्तावेजों को आखिरी दस्तावेज मानने से इनकार किया गया तो इसका विरोध शुरू हुआ था। कुछ इसी अंदाज में पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूछ लिया है कि पासपोर्ट बनाने से पहले पुलिस जब व्यक्ति का सत्यापन करती है तो आखिर वह किसका सत्यापन करती है और क्यों करती है? उनका यहां तक कहना है कि इससे लोगों के मन में यह भी संदेह उत्पन्न हो सकता है कि गैर भारतीयों को भी पासपोर्ट दिए जा रहे हैं? इन पंक्तियों के लिखे जाने तक भारत सरकार की ओर से नगारकिता के प्रमाण को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब पासपोर्ट मान्य नहीं, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर भरोसा नहीं और पैन कार्ड मान्य नहीं तो फिर आम नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे साबित करे। निश्चित तौर पर इसका भी सरकारी व्यवस्था में है। 20 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा था, 'जन्म की तारीख और जन्म-स्थान से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।' इसमें रिलीज में कहा गया था कि जन्म की तारीख और जन्म स्थान से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, इन दस्तावेजों के बारे में आखिरी रूप से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसमें वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, इंश्योरेंस के कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर से जुड़े दस्तावेज या सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ऐसे ही अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में और भी दस्तावेज़ शामिल किए जा सकते हैं ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को बेवजह परेशानी न हो। बेशक कानून की भाषा अलग होती है और लोक का शब्द संसार अलग, लेकिन दोनों के बीच संतुलन होना ही चाहिए। लोक की समझ अपने तंत्र के लिए बेहतर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि लोक और कानून की भाषा के बीच के अंतर को पाट लिया जाए। अन्यथा गलतफहमियां होती रहेंगी और आखिरकार इससे नुकसान लोकतंत्र का होगा।

भयावह जलवायु संकट







सरोज वार्ता/ब्यूरो

ब्राजील के बेलेम में संपन्न कॉप-30 सम्मेलन में जारी 'जलवायु जोखिम सूचकांक-2026' रिपोर्ट में उल्लेखित आंकड़े भारत से जुड़ी जलवायु संकट की भयावह तस्वीर दिखाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया में जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित पहले दस देशों में शामिल हैं। यह डराने वाली रिपोर्ट बताती है कि पिछले तीन दशक में भारत में आई जलवायु संकट से जुड़ी आपदाओं में करीब अस्सी हजार लोगों को मौत का ग्रास बनना पड़ा। इतना ही नहीं करीब 170 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान भी देश को उठाना पड़ा है। ये आंकड़े जलवायु संकट के देश पर पड़ने वाले घातक प्रभावों की तस्वीर उकेरते हैं। जो बताते हैं कि इस संकट से उबरने के प्रयासों में और तेजी लाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर इस दिशा में यदि युद्ध स्तरीय प्रयास तेज नहीं किए जाते तो भविष्य में परिणाम और घातक हो सकते हैं। ये प्रयास केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी तेज करने की जरूरत है। जागरूकता अभियानों में भी तेजी लाने की जरूरत है। इस संकट ने फसलों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव से हमारी खाद्य शृंखला पर भी संकट मंडरा सकता है। हमें 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का पेट भरने के लिये इस दिशा में शोध-अनुसंधान के साथ व्यापक किसान जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने की जरूरत है। दरअसल, जलवायु संकट के चलते देश में जो ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके पीछे लगातार आ रहे चक्रवात, कुछ इलाकों में सूखे और बाढ़ की लगातार पैदा होती स्थितियां हैं। जाहिर इसके मूल में तेजी से बढ़ता वातावरण का तापमान ही है। जिसका मुख्य कारक ग्लोबल वार्मिंग ही है। निश्चित रूप से भारत में जलवायु संकट की स्थिति लगातार विकट होती जा रही है। निर्विवाद रूप से देश के सामने पैदा मौसमी आपदाओं से हमारे विकास में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। जो जीविका संकट भी पैदा कर रहा है। दरअसल, बेलेम में संपन्न कॉप-30 सम्मेलन में जारी की गई 'जलवायु जोखिम सूचकांक-2026' रिपोर्ट उन संकटपूर्ण स्थितियों का भी खुलासा करती है जो जलवायु संकट के कारण पैदा हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि पिछले वर्ष भारी बारिश व विनाशक रूप में आई बाढ़ से देश में करीब अस्सी लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसमें दो राय नहीं कि भारत सरकार ने जलवायु संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष अपनी प्रतिबद्धता बार-बार जतायी है। इस संकट से उबरने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्प को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया है। देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में नवीकरणीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। देश वनों का दायरा को भी बढ़ाने की जरूरत है। विकास देश की प्राथमिकता है, लेकिन यह विकास वनों के विनाश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। साथ ही इस दिशा में जो भी कदम उठाये जाएं उनका प्रभाव जमीनी स्तर पर कितना हो रहा है, इस बात का लगातार मूल्यांकन भी जरूरी है। साथ ही रीति-नीतियों को प्रभावी तरीकों से अमलीजामा पहनाने की जरूरत होगी। जिसके लिये लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाइयों ग्राम पंचायत से लेकर शहरी निकायों को भी शामिल करने की जरूरत होगी। दरअसल, जलवायु परिवर्तन से उपजा संकट केवल भारत की ही चुनौती नहीं है। यह एक वैश्विक संकट है। जो इस बात से पता चलता है कि पिछले तीन दशकों में नौ हजार से अधिक मौसमी आपदाओं ने पूरी दुनिया में आठ लाख से अधिक लोगों को असमय काल का ग्रास बनाया है। लेकिन इस संकट की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इसकी सबसे बड़ी कीमत वे विकासशील व गरीब देश चुका रहे हैं, जिनकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे कम भूमिका रही है। दुर्भाग्य से विकासशील देश जहां इन संकटों की दृष्टि से जहां ज्यादा संवेनशील हैं, वहीं इससे मुकाबले के लिये उनके संसाधन सीमित हैं। उनके प्रतिरोध की क्षमता सीमित है। जिन्हें तत्काल व्यापक वित्तीय सहायता की जरूरत है। ऐसे में विकसित देशों का नैतिक दायित्व बनता है कि उनका सहयोग सिर्फ विकासशील देशों को वित्तीय व तकनीकी सहयोग तक सीमित न रहे। साथ ही वे अपने कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाएं।

नई भाजपा के रोल मॉडल हैं योगी, हेमंत और शुभेंदु!



प्रो. संजय द्विवेदी

उत्तर प्रदेश एक ऐसे मुख्यमंत्री से रूबरू है, जिसे राजनीति के मैदान में बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। उनके बारे में यह ख्यात था कि वे एक खास वर्ग की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनकी राजनीतिक शैली से पूरी तरह सहमत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह अपनी पकड़ बनाई है और देश में एक अलग माडल खड़ा दिया है, वह सर्वत्र चर्चा का विषय है। इससे यह भी साबित हो रहा है कि 'अपनी राजनीति' के प्रति भाजपा का आत्मदैन्य कम हो रहा है। वहीं असम में हेमंत विश्वशर्मा उम्मीदों का चेहरा बनकर उभरे हैं, असम में तीसरी बार सरकार बनाकर भाजपा ने पूर्वोत्तर में इतिहास रच दिया है। इसी तरह गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति से पश्चिम बंगाल की विजय ऐतिहासिक कही जा रही है और वहां बने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ फैसलों ने जनविश्वास की हिलोरें पैदा की हैं। जड़ता को तोड़कर एक नई उम्मीद बनी है। केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगमन ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदलकर रख दिया है।

> **उत्तर प्रदेश की 'आदित्यनाथ परिघटना' दरअसल भाजपा की वैचारिक हीनग्रंथि से मुक्ति को स्थापित करती नजर आती है। नरेंद्र मोदी के राज्यारोहण के बाद योगी आदित्यनाथ का उदय भारतीय राजनीति में एक अलग किस्म की राजनीति की स्वीकृति का प्रतीक है। एक धर्मप्राण देश में धार्मिक प्रतीकों, भगवा रंग, सन्यासियों के प्रति जैसी विरक्ति मुख्यधारा की राजनीति में दिखती थी, वह अन्यत्र दुर्लभ है।**

वैचारिक हीनग्रंथि से बाहर आई भाजपा- भाजपा का आज तक का ट्रैक हिंदुत्व का वैचारिक और राजनीतिक इस्तेमाल कर सत्ता में आने का रहा है। देश की राजनीति में चल रहे विमर्श में भाजपा बड़ी चतुराई से इस कार्ड का इस्तेमाल तो करती थी, किंतु उसके नेतृत्व में इसे लेकर एक हिचक बनी रहती थी। वो हिचक अटल जी से लेकर आडवानी तक हर दौर में दिखी है। भाजपा का हर नेता सत्ता पाने के बाद यह साबित करने में लगा रहता है वह अन्य दलों के नेताओं के कम 'सेकुलर' नहीं है। उत्तर प्रदेश की 'आदित्यनाथ परिघटना' दरअसल भाजपा की वैचारिक हीनग्रंथि से मुक्ति को स्थापित करती नजर आती है। नरेंद्र मोदी के राज्यारोहण के बाद योगी आदित्यनाथ का उदय भारतीय राजनीति में एक अलग किस्म की राजनीति की स्वीकृति का प्रतीक है। एक धर्मप्राण देश में धार्मिक प्रतीकों, भगवा रंग, सन्यासियों के प्रति जैसी विरक्ति मुख्यधारा की राजनीति में दिखती थी, वह अन्यत्र दुर्लभ है। भाजपा जैसे दल भी इस सेकुलर विकार से कम ग्रस्त न थे। धर्म और धर्माचार्यों का इस्तेमाल, धार्मिक आस्था का दोहन और सत्ता पाते ही सभी धार्मिक प्रतीकों से मुक्ति लेकर सारी राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण में लग जाती थी। प्रधानमंत्रियों समेत जाने कितने सत्ताधीशों के ताज जामा मस्जिद में झुके होगें, लेकिन हिंदुत्व के प्रति उनकी हिचक निरंतर थी। यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं की एक समय में दीनदयाल

जी उदार थे, तो अटलजी और बलराज मधोक अपनी वक्रता के चलते उग्र नेता माने जाते थे। अटलजी का दौर आया तो लालकृष्ण आडवाणी उग्र कहे जाने लगे, फिर एक समय ऐसा भी आया जब आडवानी उदार हो गए और नरेंद्र मोदी उग्र मान जाने लगे। आज की व्याख्याएं सुनें- नरेंद्र मोदी उदार हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह उग्र माने जाने लगे हैं। अब तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी आदित्यनाथ की परंपरा के मुख्यमंत्री कहे जाने लगे हैं।

सेकुलर संक्रमण से मुक्ति से मिली नई पहचान- यह मीडिया, बौद्धिकों की अपनी रोज बनाई जाती व्याख्याएं हैं। लेकिन सच यह है कि अटल, मधोक, आडवानी, मोदी, अमित शाह या आदित्यनाथ, हेमंत विश्वशर्मा और शुभेंदु अधिकारी कोई अलग-अलग लोग नहीं है। एक विचार के प्रति समर्पित राष्ट्रनायकों की सूची है यह। इसमें कोई कम जा ज्यादा उदार या कठोर नहीं है। किंतु भारतीय राजनीति का विमर्श ऐसा है जिसमें वास्तविकता से अधिक ड्रामे पर भरोसा है। भारतीय राजनेता की मजबूरी है कि वह टोपी पहने, रोजा भले न रखे किंतु इफ्तार की दावतें दे। आप ध्यान दें सरकारी स्तर पर यह प्रहसन लंबे समय से जारी रहा है। भाजपा भी इसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। उसमें भी इस तरह के रोग हैं। वह भी राष्ट्रनीति के साथ थोड़े तुष्टिकरण को गलत नहीं मानती। जबकि उसका अपना नारा रहा है सबको न्याय, तुष्टिकरण किसी का नहीं। उसका एक नारा यह भी रहा है- 'राम, रोटी और इंसाफ।

' लंबे समय के बाद भाजपा में अपनी वैचारिक लाइन को लेकर गर्व का बोध दिख रहा है। असरे बाद वे भारतीय राजनीति के सेकुलर संक्रमण से मुक्त होकर अपनी वैचारिक भूमि पर गरिमा के साथ खड़े दिख रहे हैं। समझौतों और आत्मसमर्पण की मुद्राओं के बजाए उनमें अपनी वैचारिक भूमि के प्रति हीनताग्रंथि के भाव कम हुए हैं। अब वे अन्य दलों की नकल के बजाए एक वैचारिक लाइन लेते हुए दिख रहे हैं। दिखावटी सेकुलरिज्म के बजाए वास्तविक राष्ट्रीयता के उनमें दर्शन हो रहे हैं। मोदी जब एक सौ चालीस करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं तो बात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से ऊपर चली जाती है। यहां देश सम्मानित होता है, एक नई राजनीति का प्रारंभ दिखता है। एक भगवाधारी संन्यासी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो वह एक नया संदेश देता है। वह संदेश त्याग का है, परिवारवाद के विरोध का है, तुष्टिकरण के विरोध का है, सबको न्याय का है।

भारतीयता का विमर्श अब केंद्रीय विमर्श- आजादी के बाद के सत्तर सालों में देश की राजनीति का विमर्श भारतीयता और उसकी जड़ों की तरफ लौटने के बजाए घोर पश्चिमी और वामपंथी रह गया था। जबकि बेहतर होता कि आजादी के बाद हम अपनी ज्ञान परंपरा की और लौटते और अपनी जड़ों को मजबूत बनाते। किंतु सत्ता, शिक्षा, समाज और राजनीति में हमने पश्चिमी तो, कहीं वामपंथी विचारों के आधार पर चीजें खड़ी कीं। इसके कारण हमारा अपने समाज से ही रिश्ता कटता चला गया। सत्ता और जनता की दूरी और बढ़ गयी। सत्ता दाता बन बैठी और जनता याचक। सेवक मालिक बन गए। ऐसे में लोकतंत्र एक छद्म लोकतंत्र बन गया। यह लोकतंत्र की विफलता ही है कि हम सत्तर साल के बाद सड़कें बना रहे हैं। यह लोकतंत्र की विफलता ही है कि हमारे अपने नौजवानों ने भारतीय राज्य के खिलाफ बंदूकें उठा रखी थीं। गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़संकल्प की बदौलत आज माओवादी आतंक का अंत भी हमने देखा। पिछले सत्तर सालों में लोकतंत्र की विफलता की ये कहानियां सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं। राजनीतिक तंत्र के प्रति उठा भरोसा भी साधारण नहीं था। आज ऐसा लगता है कि राजनीति से कुछ हो सकता है। मोदी,शाह, आदित्यनाथ भरोसे के प्रतीक बन गए। इसका मतलब यह भी है कि ये कुछ कह रहे हैं तो करेंगें भी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ देश की इन्हीं उम्मीदों के चेहरे हैं। तीनों अंग्रेजी नहीं बोलते। तीनों जन-मन-गण के प्रतिनिधि हैं। यह भारतीय राजनीति का बदलता हुआ चेहरा है। क्या सच में भारत खुद को पहचान रहा है ? वह जातियों, पंथों, क्षेत्रों की पहचान से अलग एक बड़ी पहचान से जुड़ रहा है- वह पहचान है भारतीय होना, राष्ट्रीय होना। एक समय में राजनीति हमें नाउम्मीद करती हुयी नजर आती थी। बदले समय में वह उम्मीद जगा रही है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो भरोसा जगाते हैं। एक आकांक्षावान भारत बनता हुआ दिखता है। यह आकांक्षाएं राजनीति दलों के एजेंडे से जुड़ पाएं तो देश जल्दी और बेहतर बनेगा। राजनीतिक विमर्श और जनविमर्श को साथ लाने की कवायद हमें करनी ही होगी। जल्दी बहुत जल्दी। यह जितना और जितना जल्दी होगा भारत अपने भाग्य पर इठलाता दिखेगा।



आप सभी का धन्यवाद

सरोज वार्ता के बढ़ते कदम

सरोज के सफल 12 वर्ष का सफ़र



सरोज वार्ता

आप सभी सुधी पाठक, विज्ञापनदाताओं का हार्दिक आभार प्रकट करता है जिन्होने सरोज वार्ता का हर कदम पर साथ दिया

यूपी का विधाता अन्नदाता



3.12 करोड़ किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
₹99 हजार करोड़+
की राशि अंतरित

रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान
₹3.15 लाख करोड़+
गन्ना मूल्य ₹315 से बढ़ाकर
₹400 प्रति क्विंटल

बिचौलिया मुक्त बाजार
ई-मंडी में 6.42 करोड़+ पर्चियां

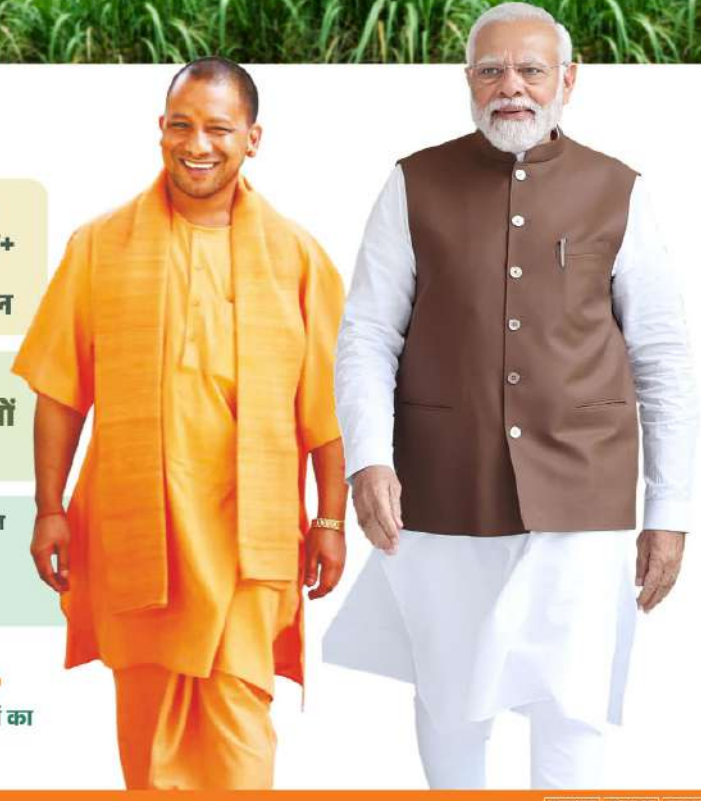
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
3.53 करोड़+ किसानों
को क्षतिपूर्ति

किसानों को कार्बन क्रेडिट धनराशि वितरित करने वाला
प्रथम राज्य

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत
86 हजार+
सोलर पंपों की स्थापना

निःशुल्क बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी हेतु
'उत्तर प्रदेश मंडी भाव'
मोबाइल ऐप

86 लाख+
लघु/सीमांत किसानों का
फसल ऋण माफ



विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

1 NATION GRID FREQUENCY

पावरग्रिड
POWERGRID

Transmitting Power, Transforming Lives

One of the World's Largest Electric Power Transmission Utility

POWERGRID's areas of operations



TRANSMISSION

- **Transmission Lines -** 1,84,960 ckm
- **Sub-stations -** 291
- **Transformation Capacity -** 6,24,016 MVA



CONSULTANCY

- **Transmission related consultancy:** Global footprints in 25 countries
- **POWERGRID Academy of Leadership:** 550+ courses catering to professionals across the world



TELECOM

- **Owns and Operates** >1 lakh km of **telecom network**
- **Leading consultant in NKN and NOFN** implementation



FUTURE READY

- **Data Centre Services**
- **Solar Power Generation**
- **Battery Energy Storage System**
- **EV Charging Infrastructure**

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Corporate Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001, Haryana. Tel. 0124-2571700-719

Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

CIN: L40101DL1989GOI38121 www.powergrid.in

Follow Us: